लखनऊ

बुधवार, 5 अगस्त , 2026

वर्ष : 11 । अंक: 336

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

क्रोध एक ऐसा तेज़ाब है, जो उस पात्र को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है जिसमें वह रखा जाता है।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

संक्षेप

असम में नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में 3 किशोर गिरफ्तार, फांसी की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन

दिसपुर। असम के हैलाकांडी जिले में 15 वर्षीय किशोरी की कथित दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आगे भी कुछ गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई है। पुलिस के अनुसार, मृतका आरोपियों में से एक के साथ रिश्ते में थी। किशोरी का शव राष्ट्रीय राजमार्ग-6 (एनएच-6) के पास स्थित उसके घर में मिला था। परिजनों का आरोप है कि उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने रविवार को पांच युवकों को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद सोमवार को 17 से 19 वर्ष आयु के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हैलाकांडी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने बताया कि एक आरोपी की उम्र करीब साढ़े 17 वर्ष है। पुलिस ने अदालत से उसे वयस्क मानकर मुकदमा चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। मृतका की मां ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य एक दावत में गए थे। वहां किशोरी की अपने चचेरे भाई के साथ कहासुनी हो गई, जिसके बाद वह रात करीब 10:30 बजे अकेले घर लौट आई। लगभग एक घंटे बाद जब परिवार घर पहुंचा तो वह मृत मिली। परिजनों ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और उनसे पूछताछ जारी है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी घर और परिवार की परिस्थितियों से परिचित थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटना के बाद हैलाकांडी और बराक घाटी क्षेत्र में लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने असम और मिजोरम को जोड़ने वाले एनएच-6 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा, यहां तक कि फांसी देने की मांग की।

लिव-इन रिलेशनशिप पर एससी का बड़ा फैसला, बिना शादी साथ रहने वाली महिलाओं को भी मिलेगा 498ए का संरक्षण

नई दिल्ली, एजेंसी। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब अगर कोई जोड़ा बिना शादी किए पति-पत्नी की तरह साथ रह रहा है, तो उनके रिश्ते पर भी घरेलू हिंसा और क्रूरता से जुड़े कड़े कानून लागू होंगे। शीर्ष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए का दायरा बढ़ाते हुए साफ कर दिया है कि 'शादी जैसे रिश्ते' में रहने वाली महिलाओं के साथ अगर जुल्म या क्रूरता होती है, तो उनके पुरुष पार्टनर और उसके रिश्तेदारों पर भी 498ए के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इस बड़े फैसले पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि धारा 498ए का डंडा हर लिव-इन रिलेशनशिप पर नहीं चलेगा। यह नियम केवल उन्हीं रिश्तों पर लागू होगा जो पूरी तरह से 'शादी जैसे रिश्ते' की श्रेणी में आते हैं।

'सपा ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई'

विधानसभा में बवाल पर भड़के योगी, बोले- सपा को संविधान पर भरोसा नहीं

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में हेराफेरी के आरोपों के बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की आलोचना करते हुए इसे भारत की आस्था पर हमला बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज विधानसभा में पूरे राज्य ने समाजवादी पार्टी और विपक्ष का व्यवहार देखा। यह व्यवहार न केवल सदन का अपमान है, बल्कि अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी है। सदन नियमों और परंपराओं से चलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यप्रणाली और कामकाज के नियमों के नियम 59 के तहत यह पहले से तय है कि किसी ट्रिब्यूनल या आयोग के पास लंबित किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में, यदि अध्यक्ष को लगता है कि चर्चा से जांच प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी, तो वे अनुमति दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह भी आश्वासन दिया था कि वे जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, उनके लिए नोटिस देंगे। अयोध्या राम मंदिर का मामला अदालत में लंबित है। मामले की गंभीरता को समझने के बावजूद, उन्होंने न केवल सदन का अपमान किया है, बल्कि अदालत की चल रही प्रक्रिया का भी अपमान करने की शर्मनाक कोशिश की है।

> सपा और विपक्ष का आचरण आज पूरे प्रदेश ने विधानसभा में देखा है। ये आचरण ना केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी है। सदन नियमों और परंपराओं से चलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के और अधिक दिखाएं
>
> मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि जिनका मुख्य मकसद ही हंगामा करना रहा हो, उन्हें लोकतांत्रिक कैसे कहा जा सकता है? वे 'हल्ला बोल' में यकीन रखते हैं। वे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। अयोध्या मामले में, जहाँ ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहाँ चंदा चोरी नहीं हुई थी; मामला चढ़ावे से जुड़ा था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा कि अखबारों और मीडिया में इस बारे में जानकारी आई है, और हम चाहते हैं कि SIT बने और जांच हो। ट्रस्ट, कोर्ट द्वारा बनाया गया एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। राज्य सरकार, ट्रस्ट के अनुरोध या कोर्ट के फैसले के बिना इस मामले में दखल नहीं दे सकती थी।

उन्होंने कहा कि 23 जून को SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ट्रस्ट ने 25 जून को FIR दर्ज कराई। FIR के बाद, सबूतों के आधार पर आठ लोगों को पकड़ा गया। कोर्ट ने आगे की कार्रवाई के लिए पूरे मामले को अपनी निगरानी में ले लिया। इस मामले में किसी संत या साधु की कोई भूमिका नहीं पाई गई। मंदिर परिसर में 1100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जिनमें से 8 लोगों की भूमिका पाई गई। संतों, साधुओं, अयोध्या धाम, राम जन्मभूमि मंदिर और कर्मचारियों को बदनाम करना बहुत हैरानी की बात है।

कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे (Infra), जन-कल्याण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 21 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में राज्य के ढांचागत विकास को नई गति देने के साथ-साथ किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए।

कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए इतना बजट

कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की बात करें तो कृषि विभाग को 13,237.76 लाख राजस्व और 15,900.00 लाख पूंजीगत विकास के लिए दिए गए हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के हिस्से में 24,480.37 लाख राजस्व और 1,005.02 लाख पूंजीगत आवंटन आया है। पशुपालन विभाग के लिए 2,497.84 लाख राजस्व व 4,486.66 लाख पूंजीगत, दुग्ध विकास विभाग के लिए 20,425.10 लाख राजस्व, मत्स्य विभाग के लिए 300.00 लाख राजस्व व 600.00 लाख पूंजीगत, तथा भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग को 200.00 लाख का राजस्व बजट मंजूर हुआ है।

बुनियादी विकास और ऊर्जा क्षेत्र में ध्यान केंद्रित

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए पेश किए गए अनुपूरक बजट में राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। औद्योगिक विकास एवं भारी उद्योगों को सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है, जिसके तहत भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए 1,30,301.92 लाख का राजस्व खर्च और 20,90,588.00 लाख (लगभग 20,905.88 करोड़) का भारी-भरकम पूंजीगत बजट मंजूर किया गया है। इसके अलावा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को 1,502.79 लाख राजस्व और 12,500.00 लाख पूंजीगत मद में दिए गए हैं, जबकि मुद्रण तथा लेखन सामग्री के पूंजीगत कार्यों हेतु 2,350.00 लाख की व्यवस्था की गई है।

लोगों का स्वास्थ्य सुधारने की भी कोशिश

इस अनुपूरक बजट में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रभाग के लिए राजस्व मद में 10.00 लाख और पूंजीगत मद में 10.00 लाख (कुल 20.00 लाख) का प्रावधान किया गया है। एलोपैथी चिकित्सा प्रभाग को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, जिसके अंतर्गत राजस्व मद में 1,10,000.00 लाख (1,100 करोड़) तथा पूंजीगत मद में 9,600.00 लाख (96 करोड़) आवंटित किए गए हैं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा प्रभाग के लिए राजस्व मद में 25.00 लाख और पूंजीगत मद में 2,300.00 लाख (23 करोड़) रखे गए हैं। इसके अलावा परिवार कल्याण प्रभाग के लिए राजस्व मद में 70,425.00 लाख (704.25 करोड़) तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाग के लिए राजस्व मद में 2,015.00 लाख (20.15 करोड़) और पूंजीगत मद में 4,050.00 लाख (40.50 करोड़) स्वीकृत किए गए हैं।

सपा सदस्यों का हंगामा लगातार जारी

उर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा सदन में अपने विभाग के एजेंडा रख रहे हैं। उधर, सपा सदस्यों का हंगामा लगातार जारी है। वह सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सपा के 'चंदा चोर कहां मिलेंगे' नारे के जवाब में भाजपा का 'टोटी चोर कहां मिलेंगे' सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। सपा विधायकों का हंगामा जारी है। वह लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सपा के सभी सदस्य वेल में मौजूद हैं।

'लज्जा भंग' या 'बेबस महिला' जैसे शब्दों का न हो इस्तेमाल, रेप केस की सुनवाई के लिए एससी की गाइडलाइंस

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई और फैसले लिखने में अधिक संवेदनशीलता अपनाने पर जोर देते हुए एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालतों को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो पीड़ित की गरिमा, संवैधानिक अधिकारों और शारीरिक स्वायत्तता का सम्मान करे।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जजों को 'प्रोसिक्यूट्रिक्स (शिकायतकर्ता महिला)', 'बेबस महिला', 'पवित्रता खो दी' और 'लज्जा भंग' जैसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। इसके बजाय 'पीड़ित', 'सर्वाइवर', 'शिकायतकर्ता', 'शारीरिक स्वायत्तता' और 'यौन हमला' जैसे तटस्थ और सम्मानजनक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए।

'जजमेंट्स एंड जेंडर: सेंसिटिविटी एंड कम्पैशन इन राइटिंग जजमेंट्स' शीर्षक वाली यह रिपोर्ट देशभर की ट्रायल अदालतों के 125 फैसलों के अध्ययन के आधार पर तैयार की गई है। इस अध्ययन में विभिन्न राज्य या कि अकादमियों का सहयोग लिया गया। रिपोर्ट में पाया गया कि

मामलों में न्यायिक भाषा और व्यवहार में संवेदनशीलता की कमी देखने को मिली। समिति ने कहा कि निष्पक्षता, सम्मान और तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए अदालतों को पीड़ित को दोषी ठहराने वाले सवालों और रूढ़िवादी टिप्पणियों से बचना चाहिए। साथ ही, पीड़ितों को आरोपी के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। समिति ने विशेष रूप से चिंता जताई कि बेहोश महिलाओं से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामलों में कई बार न्यायिक टिप्पणियां बलात्कार से जुड़े मिथकों को बढ़ावा देती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे मामलों में आरोपी के व्यवहार पर ध्यान देने के बजाय अक्सर पीड़ित की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाते हैं, जो न्याय की भावना के विपरीत है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सम्मान, शर्म, पवित्रता, संकोच और शुद्धता जैसे शब्द पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाते हैं, जो महिला की गरिमा को उसकी यौन पवित्रता या परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं। इसके बजाय न्यायिक तर्क का आधार सहमति, गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता और सं वै धा नि क अधिकार होने चाहिए।

जोधपुर जेल में बंद आसाराम को 13 साल बाद बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 20 दिन की पैरोल को दी मंजूरी

जोधपुर, एजेंसी। जोधपुर जेल में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 87 वर्षीय आसाराम को 13 साल बाद पहली बार 20 दिन की पैरोल मिल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि पैरोल देने से इनकार करने के लिए प्रस्तुत की गई आशंकाओं का कोई ठोस आधार रिकॉर्ड पर नहीं है।

आसाराम की ओर से अधिवक्ता कालूराम भाटी और यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पैरोल आवेदन को अस्वीकार करने की अनुशंसा की गई थी। पुलिस ने आशंका जताई थी कि पैरोल मिलने पर वह फरार हो सकता है। सरकार ने यह भी कहा कि उसके खिलाफ राजस्थान के बाहर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और गुजरात की एक अदालत भी उसे दोषी ठहरा चुकी है। सरकार ने अदालत के समक्ष यह तर्क भी रखा कि आसाराम उपचाराधीन है तथा मेडिकल अधिकारी ने पैरोल पर रिहाई के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं दिया है। इसके अलावा शिकायतकर्ता के परिवार की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर आशंका जताई गई।

'जनता तंग आ चुकी है' : बिहार-एमपी के उपचुनाव में भाजपा की हार पर प्रियंका गांधी वाड्रा का तंज

नई दिल्ली, एजेंसी। बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हार के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन नतीजों से साफ है कि लोग अब भाजपा से तंग आ चुके हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली पर कब्जा कर लिया। वहीं, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। जब संसद परिसर में पत्रकारों ने उपचुनाव के नतीजों पर प्रियंका गांधी से सवाल किया, तो उन्होंने कहा, यह साफ है कि जनता भाजपा से थक चुकी

है और तंग आ चुकी है। अब लोग समझ रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है।

बांकीपुर में कितने वोटों से जीते प्रशांत किशोर?

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 64,151 वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। भाजपा के नीरज कुमार को 44,827 और राजद की रेखा कुमारी को 14,273 वोट मिले। लेकिन इस जीत के बीच सबसे ज्यादा चर्चा दो और उम्मीदवारों की हार की हो रही है। वजह यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार नितीश कुमार और लालू प्रसाद यादव (ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि समान नाम वाले प्रत्याशी हैं) चुनाव मैदान में उतरे थे।

गुजरात में अपनी सीट बचाने में कामयाब रही भाजपा

वहीं, गुजरात के वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपनी सीट बरकरार रखी। भाजपा उम्मीदवार सतीश गोविंदभाई पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी को 30,630 वोटों से हराया। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पहले नितिन नवीन के पास थी। उनके विधायक पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी संभालने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया।

'दीपके को तुरंत करें गिरफ्तार' : दिल्ली पुलिस से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान ने की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दीपके के सहयोगियों ने उन पर पुणे और औरंगाबाद में हमला किया था। अंसारी ने दिल्ली पुलिस के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को दी गई शिकायत में कहा कि इन दोनों घटनाओं के संबंध में पहले से दो मामले दर्ज हैं। उन्होंने पुलिस से अभिजीत दीपके को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है।

फैजान अंसारी ने एएनआई से बातचीत में कहा, 'आज मैंने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली डीसीपी को लिखित शिकायत दी है, क्योंकि मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि उनके लोगों ने मुझ पर हमला किया। मुझ पर पुणे और औरंगाबाद में हमला हुआ था। इस संबंध में पहले से दो मामले दर्ज हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस तुरंत दीपके को गिरफ्तार करे।'

वांगचुक को लेकर क्या बोले फैजान अंसारी?

अंसारी ने आगे कहा, 'मैं सही समय पर सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस को सलाम करता हूं। इससे दिल्ली का माहौल खराब होने से बच गया। दीपके जो कुछ भी कर रहे हैं, वह अपने निजी फायदे के लिए कर रहे हैं।'

किसने उठाई दीपके की विदेश में पढ़ाई पर जांच की मांग?

इससे पहले सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता भगवानराव दीपके की आय की जांच की मांग की थी। उन्होंने सवाल उठाया था कि एक जूनियर इंजीनियर (जेई) के वेतन से उनके बेटे की अमेरिका में उच्च शिक्षा का खर्च कैसे उठाया गया? आरटीआई कार्यकर्ता ने चुनाव आयोग (ईसीआई) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से भी सीजेपी की कानूनी स्थिति और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा घोषित एक करोड़ रुपये की सहायता राशि पर कर देयता की जांच की मांग की है। वहीं, सोमवार को अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे फिर से धरना देंगे।

डीजल लेकर जा रहा टैंकर बिजली के पोल से टकराया, लगी भीषण आग ; 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत

आर्यावर्त क्रांति

आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में मातम और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। गोरखपुर से डीजल लेकर बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप की ओर जा रहा एक भारी-भरकम टैंकर सोमवार को जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मालटारी-मिर्जापुर स्थित बिजली उपकेंद्र (सब-स्टेशन) के पास एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। बेकाबू टैंकर बिजली के पोल से जा टकराया, जिससे पोल पर लगा ट्रांसफार्मर सीधा टैंकर पर गिर गया और एक जोरदार धमाके के साथ उसमें भीषण आग लग गई।

हादसा इतना खौफनाक था कि धमाके के तुरंत बाद टैंकर से आग की ऊंची-ऊंची और विकराल लपटें उठने लगीं। आसपास मौजूद ग्रामीण और राहगीर चाहकर भी टैंकर के पास नहीं जा सके और उन्हें दूर से ही इस भयावह मंजर को देखने पर मजबूर होना पड़ा। देखते ही देखते आग ने पूरे टैंकर को अपनी आगोश में ले लिया और उसमें मौजूद लोगों को बाहर निकलने का जरा भी मौका नहीं मिला। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग (फायर ब्रिगेड) की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाने के लिए दमकल की छह गाड़ियों को घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि, जब तक आग पूरी तरह से बुझ पाती, तब तक पूरा टैंकर जलकर खाक हो चुका था और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी थी। इस भीषण अग्निकांड में तीन लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में एक की पहचान मेहनगर थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव निवासी 26 वर्षीय प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। जवान बेटे की इस दर्दनाक मौत की खबर जैसे ही उसके परिवार तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

देर रात तक अयोध्या के एसबीआई में रहे कृष्ण मोहन, बैंक लॉकर में चेक किया सोना-चांदी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच के बीच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव डॉ। कृष्ण मोहन देर रात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की अयोध्या ब्रांच में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बैंक के लॉकर में रखे सोने, चांदी, कीमती आभूषणों समेत अन्य कीमती वस्तुओं और उनसे जुड़े रिकॉर्ड की समीक्षा की।

मंदिर के सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के फोटोग्राफर भी उनके साथ मौजूद थे। बताया जा रहा है कि अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन सोमवार शाम अयोध्या में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की शाखा गए और देर रात तक वहां रुके। इस दौरान कीमती सामान की

एक लिस्ट तैयार की गई और बैंक लॉकर में जमा सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं की चीज़ों की तस्वीरें ली गईं।

ट्रस्ट के अकाउंट और अन्य रिकॉर्ड की जांच

सूत्रों ने बताया कि कृष्ण मोहन पिछले तीन दिनों से ट्रस्ट के अकाउंट और अन्य रिकॉर्ड की जांच-पड़ताल कर रहे थे, जिसके बाद फंड और कीमती धातुओं की अंतिम लिस्ट तैयार की गई। कृष्ण मोहन बैंक में मौजूद रहे और लॉकर में रखी प्रत्येक वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा और रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की। इस दौरान ट्रस्ट के चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन राय और जगदीश अफले भी मौजूद थे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी नई एसआईटी

कृष्ण मोहन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाई गई नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के मंगलवार से अपना काम फिर से शुरू कर सकती है। हालांकि उन्होंने बैंक के अपने दौरे के बारे में पूछे गए मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं राम मंदिर में की गई व्यवस्थाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा 'आप सभी आएं, दर्शन करें और खुद देखें। अगर कोई कमी हो, तो हमें बताएं'।

नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की नए सिरे से जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में भक्तों द्वारा दान किए गए सोने, चांदी और कीमती आभूषणों के रखरखाव और रिकॉर्ड को लेकर सवाल उठे थे। भक्तों ने अपने दान की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। अब नई SIT अपनी जांच का दायरा बढ़ाएगी। सूत्रों ने बताया कि जांच में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज के कई पहलुओं को शामिल किया जाएगा और इसमें फोरेंसिक विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

8 लोग गिरफ्तार

राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी का मामला जून के पहले हफ़्ते में सामने आया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपों की जांच के लिए 13 जून को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई। शुरू में उन्हें जांच के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। 23 जून को SIT की शुरुआती रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, 25 जून को FIR दर्ज की गई और आठ आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को गिरफ़्तार किया गया।

राज्य ताइक्वांडो चौंपियनशिप में अमीना ताइक्वांडो अकादमी का जलवा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वावधान में तथा लखनऊ जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के आयोजन में केडी सिंह बाबू स्टेडियम स्थित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चौंपियनशिप में अमीना ताइक्वांडो अकादमी, सुल्तानपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया।

प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में प्रियांशु तिवारी (78 किग्रा) और साक्षी (63 किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। दोनों खिलाड़ियों का चयन अब अक्टूबर माह में ओडिशा में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो चौंपियनशिप के लिए हुआ है, जहां वे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं सब-जूनियर वर्ग में यथार्थ मौर्य (44 किग्रा) और सत्यांश आर. श्रीवास्तव (44 किग्रा) ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। फ्रेशर वर्ग में भी अमीना ताइक्वांडो अकादमी का दबदबा देखने को मिला। विजेता वर्मा (65 किग्रा), शालिनी ओझा (49 किग्रा), अनन्या वर्मा (18 किग्रा), सारांश एस. निर्मल (36 किग्रा), विधान वर्मा (46 किग्रा), वैष्णवी चौरसिया (35 किग्रा), माही गौतम (29 किग्रा), अनवी (43 किग्रा) तथा अलंकृता लाल (27 किग्रा) ने अपने-अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर अकादमी का परचम लहराया। इसी वर्ग में समीक्षा श्रीवास्तव (43 किग्रा), महक सोनी (57 किग्रा), शालिनी (38 किग्रा), विवाश्वत (25 किग्रा) तथा हर्ष गौतम (21 किग्रा) ने रजत पदक अपने नाम किए, जबकि वैभव चौरसिया (24 किग्रा) ने कांस्य पदक जीतकर अकादमी की उपलब्धियों में एक और सफलता जोड़ी। अकादमी की मुख्य प्रशिक्षक एवं राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता अमीना बानो ने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता नियमित अभ्यास, अनुशासन और कठिन परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि राष्ट्रीय चौंपियनशिप के लिए चयनित खिलाड़ी भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सुल्तानपुर और उत्तर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर अमीना ताइक्वांडो अकादमी के अध्यक्ष शिवकुमार सिंह, उपाध्यक्ष डॉ. सुधाकर सिंह, कोषाध्यक्ष एडवोकेट मदन सिंह, सदस्य श्रीमती कांति सिंह (प्रधानाध्यापक) सहित खेल प्रेमियों, अभिभावकों और जनपदवासियों ने सभी पदक विजेताओं को बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।

चेहल्लुम के जुलूस में उमड़ी भीड़ नम आंखों के साथ या हुसैन अलविदा की गूंजी आवाजें

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। शिया बाहुल्य क्षेत्रों अमहट गोराबारिक तुराबखानी अलीगढ़ अलीनगर मेड़ई खां का पुरवा ऊंचा हसनपुर मनियारपुर जूडूपुर प्रतापपुर मनियारी भाईं लौहर दक्षिण पीथापुर खैराबाद सैदपुर हयातनगर कोटवा सुरौली मूंगर बेलहरी प्यारेपुर कादीपुर सैदखानपुर चुनहा करौंदिया माल्हा वलीपुर कारीभीट इसौली धवरहरा ताजखानपुर अफलेपुर बंधुआ खुर्द सरैया बरूआ प्यारे पुर बालचंद पट्टी सजैया करीमपुर में चेहल्लुम के अवसर पर ताजिया का जुलूस निकाला गया। खास कर अमहट में सभी इमाम बारगाहों की मजलिस के बाद लगभग दिन में 12 बजे से अंजुमन जीनतुल अजहा कदीम अंजुमन जीनतुल अज अंजुमन जीनतुल अजा रजिस्टरड अलीगढ़ अमहट अंजुमन असगरिया कदीम गोराबारिक अमहट अंजुमन पंजतनी तुराबखानी अंजुमन असगरिया गोराबारिक अमहट अंजुमन कमर बनी हाशिम नौहा मातम करते हुए अमहट का ताजिया का जुलूस उठकर अमहट चौराहे से अमेठी रोड होता हुआ कर्बला अमहट पर जुलूस शाम 6-30 पर समाप्त हुआ और ताजिया सिपुर्दे खाक क्रिया गया जगह जगह पर जायरीनों के लिए सबील लगा यी गयी प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा जिससे जुलूस कामयाब रहा। यह जानकारी हैदर अब्बास खान अध्यक्ष हुसैनी शिया वेलफेयर एसोसिएशन सुल्तानपुर ने दी है।

विधायक विनोद सिंह ने किया पलटवार, महिला व उसके पति पर धोखाधड़ी के आरोप

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो प्रकरण में सुल्तानपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए चरित्र संबंधी आरोपों को निराधार और मनगढ़ंत बताया है। विधायक का कहना है कि आरोप लगाने वाली महिला और उसका पति पहले से ही धोखाधड़ी के आरोपी हैं तथा उनके विरुद्ध लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। उनका आरोप है कि गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।

विधायक विनोद सिंह के अनुसार कोतवाली देहात क्षेत्र के बेलासदा निवासी शशांक पांडेय और उनकी पत्नी सोनिया उर्फ सोनी पांडेय लखनऊ स्थित उनके अपार्टमेंट में किराए पर रहते थे। विधायक का आरोप है कि शशांक ने स्वयं को प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताते हुए एफसीआई का वेयरहाउस दिलाने का भरोसा दिया और इस संबंध में कुछ दस्तावेज तैयार कराए। बाद में केंद्रीय भंडारण निगम के नाम से भेजा गया अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) संदिग्ध लगा। जांच कराने पर वह कथित रूप से फर्जी पाया गया। विधायक का कहना है कि इसके बाद दोनों पति-पत्नी ने फोन बंद कर दिया और आवास छोड़ दिया। इस मामले में उन्होंने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। विनोद सिंह ने यह भी दावा किया कि आरोपित पक्ष ने एफआईआर निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन याचिका खारिज हो गई। उनका आरोप है कि इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उनकी पत्नी को आगे कर उन पर चरित्र संबंधी आरोप लगाए गए। विधायक ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उल्लेखनीय है कि यह विधायक विनोद सिंह का पक्ष है। दूसरी ओर महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। मामले की सत्यता और अंतिम निष्कर्ष जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होंगे।

अमहट मंडी में सफाई टेंडर लटकने से जलभराव

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। अमहट एक तरफ जहां शासन-प्रशासन संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाकर साफ-सफाई और जागरूकता का ढिंढोरा पीट रहा है, वहीं दूसरी ओर अमहट मंडी परिसर में घोर प्रशासनिक लापरवाही का नजारा देखने को मिल रहा है। मंडी समिति की घोर अनदेखी और अनियमितताओं के चलते पूरा मंडी परिसर जलमग्न हो चुका है। नाले-नालियों की सफाई का टेंडर महीनों से अटका पड़े होने के कारण नालियों का बदबूदार और दूषित पानी अब पूरी मंडी में भर गया है।

मंडी परिसर में बारिश के कारण जलभराव के बीच सब्जियां गंदे पानी में तैरती नजर आई स्थिति इतनी भयावह है कि बिक्री के लिए रखी गई सब्जियां इसी दूषित और बदबूदार पानी में तैरती नजर आ रही हैं। दूषित पानी में डूबी सब्जियों की खुलेआम बिक्री से आम जनता के स्वास्थ्य पर सीधा खतरा मंडरा रहा है, जिससे

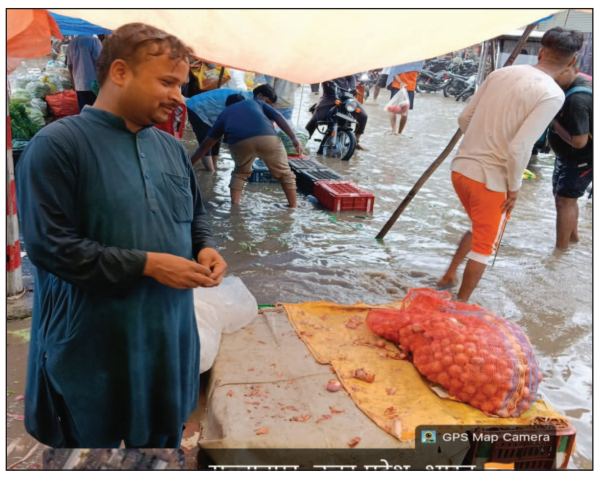

संक्रामक बीमारियों का फैलाव तय माना जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि मंडी परिसर में जल निकासी और साफ-सफाई की व्यवस्था लंबे समय से ध्वस्त है। मंडी प्रशासन की उदासीनता का आलम यह है कि नाले-नालियों की सफाई का टेंडर कागजों में ही महीनों से लटका हुआ है। बजट और कागजी लिखापढ़ी के खेल में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है। पहली ही बारिश या नालियों के ओवरफ्लो होने से पूरी मंडी तालाब का रूप ले लेती है। प्रदेश भर में संचारी रोगों (जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और हैजा) से बचाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकाय जलजमाव रोकने तथा साफ-सफाई के बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। ऐसे में अमहट मंडी की यह बदहाली प्रशासनिक दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। मंडी जैसी जगह पर, जहां हजारों लोगों की आवाजाही होती है और पूरे क्षेत्र के लिए खान-पान की सामग्री सप्लाई होती है, वहां जमा यह दूषित पानी संक्रामक बीमारियों को सीधा आमंत्रण दे रहा है। हम हर महीने मंडी शुल्क और टैक्स देते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर हमें गंदगी और बीमारी मिल रही है। टेंडर प्रक्रिया कब पूरी होगी, इसका जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं है। अगर जल्द ही जलभराव और गंदगी की समस्या से निजात नहीं मिली। क्या जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़ी बीमारी के फैलने का इंतजार कर रहे हैं? संचारी रोग अभियान के दौरान मंडी परिसर की यह दुर्दशा सीधे तौर पर संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली और नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जनता और व्यापारियों की मांग है कि तत्काल प्रभाव से वैकल्पिक व्यवस्था कर जल निकासी कराई जाए और लटके पड़े सफाई टेंडर को जल्द से जल्द हरी झंडी दी जाए।

दो साल पहले बनी 4 करोड़ की कोठी पर 22 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स! 12 करोड़ का वाटर टैक्स देख सपा नेता के उड़े होश

आर्यावर्त संवाददाता

सहारनपुर। सहारनपुर में नगर निगम की टैक्स निर्धारण व्यवस्था का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वार्ड नंबर-2 के रामनगर स्थित मल्हीपुर रोड पर रहने वाले समाजवादी पार्टी (सपा) नेता फरहाद गाड़ा के परिवार को नगर निगम की ओर से जीआईएस (GIS) सर्वे के आधार पर ऐसा प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस मिला, जिसे देखकर परिवार के लोग हैरान रह गए। नोटिस में मकान की वास्तविक कीमत से कई गुना अधिक हाउस टैक्स और जलकर का बकाया दर्शाया गया है।

फरहाद गाड़ा के अनुसार उनकी कोठी करीब 816 गज में बनी है। इसका निर्माण लगभग दो वर्ष पहले हुआ था और उनका परिवार पिछले एक साल से यहां रह रहा है। उन्होंने बताया कि मकान की मौजूदा बाजार कीमत करीब 4 करोड़ रुपये है, लेकिन नगर निगम की ओर से भेजे गए नोटिस में 22 करोड़ रुपये से

अधिक का संपत्ति कर निर्धारित कर दिया गया। इतनी बड़ी टैक्स राशि देखकर पूरा परिवार सदमे में आ गया।

नोटिस में 12 करोड़ रुपये का वाटर टैक्स भी लगा दिया गया है। परिवार का कहना है कि यह दावा पूरी तरह अव्यावहारिक और तथ्यहीन है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी राशि का पानी एक सामान्य परिवार के लिए इस्तेमाल करना संभव ही नहीं है।

नोटिस मिलने के बाद परिवार के लोगों ने नगर निगम से संपर्क किया। परिवार का आरोप है कि निगम की लापरवाही और डेटा एंट्री में हुई गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जीवनभर की कमाई से बनाए गए मकान पर उसकी कीमत से कई गुना अधिक टैक्स का नोटिस भेजना बेहद गंभीर मामला है। यदि जल्द ही इस गलती को नहीं सुधारा गया तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे।

नगर निगम ने बताया टाइपिंग या डेटा एंट्री की गलती

इस पूरे मामले पर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह टाइपिंग या डेटा एंट्री की त्रुटि प्रतीत होती है। अधिकारियों के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी गई है और यदि कोई गलती पाई जाती है तो उसे तत्काल ठीक किया जाएगा। हालांकि, परिवार का कहना है कि इतनी बड़ी चूक को केवल "टाइपिंग मिस्टेक" बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

GIS सर्वे और कर निर्धारण प्रक्रिया पर उठे सवाल

इस घटना के बाद नगर निगम की जीआईएस सर्वे प्रणाली, कर निर्धारण प्रक्रिया और रिकॉर्ड की शुद्धता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि यदि डेटा एंट्री में इतनी बड़ी गलती हो सकती है, तो अन्य संपत्तियों के टैक्स निर्धारण पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि नगर निगम इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित परिवार को कब तक राहत मिलती है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला : महिपाल सिंह ने एसआईटी को भेजे ई-मेल में बताया

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जांच जारी है। इस बीच ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) को लिखित शिकायत भेजी है। जिसमें उन्होंने ट्रस्ट पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व व्यवस्था प्रभारी टिन्नू यादव समेत कुछ अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

महिपाल सिंह ने मंदिर प्रबंधन पर कई नए आरोप लगाए हैं। उन्होंने SIT को 27 जुलाई को मेल भेजा था। 25 जुलाई को SIT ने उनसे संपर्क किया था और ईमेल के जरिए सबूत मांगे थे। इसके बाद महिपाल सिंह ने मंडलायुक्त लखनऊ को भेजे जवाबी ई-मेल में दावा किया कि उन्होंने साल 2022 में ही कई अनियमितताओं की जानकारी दी थी। उन्होंने सभी 20 बिंदुओं की शिकायत और उपलब्ध दस्तावेज SIT को भेज दिए। महिपाल सिंह ने कहा कि उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रशासन सक्षम है और उचित जांच कर सकता है।

महिपाल सिंह ने आरोप लगाया कि करीब 3 लाख रुपये लागत वाले तीन एल्यूमिनियम-ग्लास केबिन पर 17 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। उन्होंने दावा किया कि कार्यालय को अनुबंध अवधि पूरी होने से पहले ही खाली कर दिया गया, जिससे ट्रस्ट को वित्तीय नुकसान हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि एक मुकुट गायब होने के मामले में संदिग्धों से पूछताछ के बाद कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही ये दावा भी किया कि कई संदिग्ध कर्मचारी सालों तक सेवा में बने रहे।

वित्तीय अनियमितताओं के आरोप

कारसेवकपुरम (VHP कॉलोनी) में ट्रस्ट से असंबंधित लोगों को मानदेय दिया गया।

VHP कॉलोनी में कई निर्माण कार्य ट्रस्ट की निधि से कराए गए।

विभिन्न उत्सवों और कार्यक्रमों में ट्रस्ट का पैसा खर्च किया गया।

बिना कार्य किए कई लोगों को मानदेय दिया गया

निर्माण कार्य पर सवाल

महिपाल सिंह ने मंदिर के निर्माण कार्य पर सवाल भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट मैनेजर का कार्य सिविल विशेषज्ञ की बजाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कराया गया, जिससे मंदिर निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के भुगतान रोके गए, बाद में बिल बढ़ाकर भुगतान किए गए। इसके साथ ही आरोप लगाया कि सत्यापित बिलों के भुगतान और घटिया गुणवत्ता के पत्थर ऊंची कीमत पर खरीदे गए।

चढ़ावे और दान से जुड़े आरोप

सिंधी समाज द्वारा दान की गई ईंटें गायब कर दी गईं।

दानपात्रों से निकली धातु (सोना व अन्य) कैश काउंटिंग रूम से बाहर ले जाई जाती रही।

150 किलो चांदी भेजे जाने के बावजूद 85 किलो का झूला तैयार हुआ।

भरत कुटी में बिना रसीद प्राप्त निधि की चोरी का भी आरोप लगाया।

सुरक्षा व्यवस्था पर आरोप

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी महिपाल सिंह ने बड़े आरोप लगाए। उनके मुताबिक एक निजी व्यक्ति को पुलिस का वॉकी-टॉकी उपलब्ध कराया गया।राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की यात्राओं के दौरान वह प्रतिबंधित क्षेत्र में सक्रिय रहा। आरोप है कि उसे वीआईपी दर्शन, वाहन पास और सुरक्षा व्यवस्था में अनधिकृत अधिकार दिए गए।

वीआईपी दर्शन और आर्थिक लाभ

महिपाल सिंह ने आरोप लगाया कि सुरक्षा चेक पोस्ट से बड़ी संख्या में लोगों की एंट्री कराई जाती थी। इससे आर्थिक लाभ अर्जित किया। उनका कहना है कि रामलला के श्रृंगार और प्रसाद की व्यवस्था में भी अनियमितताएं हुईं। वहीं संपत्ति और निर्माण संबंधी मामलों में उन्होंने आरोप लगाया कि स्थायी निर्माण की बजाय अस्थायी ढांचों पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि विवादित संपत्तियां खरीद कर ट्रस्ट को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया।

कैश काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप

अपनी शिकायत में महिपाल सिंह ने कैश काउंटिंग में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि नकदी गणना के दौरान गड्डियों की संख्या में हेराफेरी की जाती थी। उन्होंने ये भी कहा कि शिकायत करने के बाद उन्हें गणना प्रक्रिया से हटा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक में कम राशि का वाउचर भरवा कर गबन किया जाता था।

अन्य आरोप

ट्रस्ट में कार्य नहीं करने वाले लोगों के नाम पर भुगतान उठाया जाता था।

कारसेवकपुरम में निर्माण सामग्री दान में लेकर उसके फर्जी बिल बनाकर भुगतान लिया गया।

मंदिर निर्माण की प्रारंभिक लागत 800 करोड़ रुपये थी, जबकि खर्च 2200 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया।

खुद के बारे में महिपाल सिंह ने कहा कि वह पूर्णकालिक, निशुल्क सेवा कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि कथित गबन उजागर करने के कारण उन्हें हटा दिया गया।

सांप के डसने से दिव्यांग मजदूर की मौत, परिवार में मचा कोहराम

बल्दीराय/सुल्तानपुर। थाना धनपतगंज क्षेत्र के ग्राम पाली के मजरे पूरे सूबेदार निवासी अमरनाथ विश्वकर्मा (55), पुत्र रामू विश्वकर्मा की सांप के डसने से उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार अमरनाथ विश्वकर्मा रात लगभग 11.55 बजे घर के बाहर चारपाई पर पैर लटकाकर बैठे थे। इसी दौरान अचानक एक विषैले सांप ने उनके पैर में डस लिया। परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) धनपतगंज ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मंगलवार सुबह लगभग 4.30 बजे अमरनाथ ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

विपक्ष के आरोपों पर ए.के. शर्मा का पलटवार, बोले- रामभक्तों पर गोली चलाने वालों को नैतिक अधिकार नहीं

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए कहा कि जिन लोगों का इतिहास रामभक्तों पर गोली चलवाने और वर्षों तक श्रीराम मंदिर को उपेक्षित अवस्था में छोड़ने का रहा है, उन्हें श्रीराम और सनातन में आस्था रखने वाली सरकार पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।मंगलवार को विधानसभा के तृतीय सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के बाद सदन स्थगित होने पर पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि विपक्ष के विरोध और शोर-शराबे के बावजूद सरकार पूरी गंभीरता, संयम और दृढ़ता के साथ अपनी विधायी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के

हंगामे से सरकार के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत, सनातन परंपरा और जनभावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य विकास, सुशासन और जनकल्याण को गति देना है और वह इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि निराधार आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में लगातार व्यवधान उत्पन्न करने के प्रयासों के बावजूद सरकार ने सदन की गरिमा बनाए रखते हुए अपनी विधायी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया।मंत्री ने दोहराया कि प्रदेश सरकार जनहित, विकास और सुशासन के एजेंडे पर पूरी मजबूती से काम कर रही है और विपक्ष के राजनीतिक आरोपों से विचलित हुए बिना अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती रहेगी।

अनुपूरक बजट पर शिवपाल यादव का सरकार पर हमला: 'प्रदेश को अतिरिक्त बजट नहीं, ईमानदार नीयत और जवाबदेह शासन चाहिए'

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जसवंतनगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मूल बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करने में विफल रही है और अब अनुपूरक बजट के माध्यम से अपनी प्रशासनिक एवं वित्तीय नाकामी पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि प्रदेश को अतिरिक्त बजट की नहीं, बल्कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेह शासन व्यवस्था की आवश्यकता है।

14 अगस्त को पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस'

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस-2026' का आयोजन करेगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित होगा, जबकि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी व्यापक स्तर पर कार्यक्रम होंगे। इन आयोजनों का उद्देश्य वर्ष 1947 के भारत विभाजन की त्रासदी से नई पीढ़ी को परिचित कराना, विभाजन के दौरान प्रभावित परिवारों के संघर्ष, साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देना तथा राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का संदेश देना है।प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शनी, मौन जुलूस, शांति पाठ, व्याख्यान, परिचर्चा, कैंडल मार्च तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल इतिहास को याद करना नहीं, बल्कि युवाओं को यह बताना भी है कि विभाजन जैसी त्रासदी से देश ने क्या सीखा और राष्ट्रीय एकता का महत्व कितना बड़ा है।राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य अतिथि विभाजन विभीषिका पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री तथा विभाजन के समय विस्थापित होकर भारत आए परिवारों की स्मृतियों, दस्तावेजों, चित्रों और अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं पर आधारित होगी। प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद जीपीओ पार्क से लोकभवन तक मौन जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में दो मिनट का मौन भी रखा जाएगा।कार्यक्रम में मतुआ समुदाय के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान पर आधारित एक विशेष वृत्तचित्र का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके साथ ही विभाजन से संबंधित पुस्तकों और ऐतिहासिक दस्तावेजों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिससे आमजन और विशेष रूप से युवा पीढ़ी उस दौर की परिस्थितियों को समझ सके।सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी 75 जिलों में विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विभाजन विभीषिका पर विशेष व्याख्यान, संगोष्ठियां और चर्चाएं आयोजित की जाएं। इसके अलावा शरणार्थियों की पहली और दूसरी पीढ़ी के लोगों की भागीदारी के साथ बस्तियों, बाजारों और शिक्षण संस्थानों में मौन जुलूस, शांति पाठ और कैंडल मार्च निकाले जाएंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर संक्षिप्त संबोधन भी कराया जाएगा, ताकि विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उससे मिलने वाली सीख समाज तक पहुंच सके।इस आयोजन में विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इनमें सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश सिंधी सभा, सिंधी अकादमी, सनातनी पंजाबी महासभा तथा बंगाली समुदाय सहित अनेक संस्थाएं सहयोग करेंगी।

रामलला मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर विधानसभा में चर्चा की मांग

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने अयोध्या स्थित रामलला मंदिर में चढ़ावे और दान की कथित चोरी के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से बच रही है, जबकि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय है।विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए आराधना मिश्रा मोना ने आरोप लगाया कि भाजपा ने वर्षों तक भगवान राम और राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाया, लेकिन जब रामलला मंदिर में चढ़ावे और दान की कथित चोरी का मामला सामने आया तो सरकार जवाबदेही तय करने के बजाय चर्चा से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यह केवल चोरी का मामला नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है।उन्होंने दावा किया कि भगवान रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए देश और विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दिया। गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं ने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान किया, लेकिन अब उसी दान और चढ़ावे की कथित चोरी के आरोप सामने आने से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि विपक्ष द्वारा सदन में इस विषय पर चर्चा की मांग किए जाने के बावजूद सरकार ने उस पर सहमति नहीं दी। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष की महिला विधायकों के साथ मार्शलों द्वारा धक्का-मुक्की की गई, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री सदन में इस विषय पर चर्चा के दौरान उपस्थित क्यों नहीं रहे।आराधना मिश्रा मोना ने आरोप लगाया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और ट्रस्ट में नियुक्त लोगों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि मामले में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं तो केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के बजाय जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कथित घटनाओं से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों की भी गहन जांच आवश्यक है।कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता ने कहा कि यह मामला केवल वित्तीय अनियमितता का नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है।

विधानसभा में हंगामे पर सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव पूरे सत्र के लिए निष्कासित

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में हंगामा करने के आरोप में समाजवादी पार्टी के विधायक इंजीनियर सचिन यादव के खिलाफ अध्यक्ष ने कड़ी कार्रवाई की। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें पूरे सत्र के लिए सदन से निष्कासित करने का आदेश दिया।

साथ ही उनके आचरण के मामले को विधानसभा की आचार समिति (एथिक्स कमेटी) को भेजने की चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों के गंभीर उल्लंघन की स्थिति में सदस्यता समाप्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।सदन की कार्यवाही के दौरान हुए हंगामे और अध्यक्ष के निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया गया। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि विधानसभा की गरिमा, अनुशासन और संसदीय परंपराओं का पालन सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है और नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष के आदेश के अनुसार इंजीनियर सचिन यादव अब पूरे मानसून सत्र की शेष कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे। इसके साथ ही उनके आचरण की समीक्षा के लिए मामला आचार समिति को भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समिति मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यदि जांच में नियमों के गंभीर उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो विधानसभा के नियमों के अनुरूप विधायक की सदस्यता समाप्त करने जैसी कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है।

इस कार्रवाई के बाद सदन में कुछ समय तक राजनीतिक हलचल बनी रही। विपक्ष ने इस कदम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि सत्ता पक्ष ने सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए अध्यक्ष की कार्रवाई को आवश्यक बताया। अब सभी की नजर आचार समिति की जांच और उसकी रिपोर्ट पर रहेगी, जिसके आधार पर मामले में आगे का निर्णय लिया जाएगा।

दुबई से लौटे यात्री से 30 लाख का सोना चोरी, दो गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी की सरोजनीनगर पुलिस और दक्षिणी जोन की सर्विलांस टीम ने दुबई से लौटे एक यात्री से करीब 30 लाख रुपये मूल्य का सोना चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 203.92 ग्राम सोने का पाउडर (कैप्सूल) बरामद किया है। मामले में गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। कार्रवाई से खुश होकर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25 हजार रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।पुलिस के अनुसार बलिया निवासी महबूब आलम ने 3 अगस्त को थाना सरोजनीनगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 27 जुलाई को दुबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर दीपक वर्मा, राम प्रताप दुबे, अर्शदीप और उनके साथियों ने उन्हें अपनी कार में बैठा लिया। काफी देर तक इधर-उधर घुमाने के बाद आरोपियों ने उन्हें आलमबाग बस अड्डे के पास उतार दिया और उनका ट्रॉली बैग, पासपोर्ट, कपड़े तथा सोने का कैप्सूल लेकर फरार हो गए।मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने चार विशेष टीमें गठित कर जांच शुरू की। करीब 100 से 130 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने दीपक वर्मा और राम प्रताप दुबे को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया सोना बरामद कर लिया।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे एक अंतरराज्यीय गिरोह का हिस्सा हैं, जिसके सदस्य राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सक्रिय हैं। गिरोह खाड़ी देशों, विशेषकर दुबई में ऐसे भारतीयों को निशाना बनाता है जो किसी कारणवश जल्द भारत लौटना चाहते हैं।

पारिवारिक विवाद के बाद व्यक्ति की मौत, पत्नी और बेटे पर मारपीट का आरोप

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के निगोहां थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के बाद एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। मृतक के छोटे भाई ने आरोप लगाया है कि पत्नी और बेटे द्वारा की गई मारपीट के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।पुलिस के अनुसार मंगलवार तड़के करीब तीन बजे मीरकनगर गांव निवासी दुर्गेश कुमार ने थाना निगोहां में सूचना दी कि उनके बड़े भाई कैलाशचंद्र (54 वर्ष) का सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे घर में पत्नी लज्जावती और बड़े पुत्र शिवम उर्फ अरुण से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और आरोप है कि दोनों ने कैलाशचंद्र के साथ मारपीट कर दी, जिससे उन्हें चोटें आईं।परिजनों के अनुसार मारपीट के बाद कैलाशचंद्र की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। उन्हें तत्काल उपचार के लिए रेलवे अस्पताल, आलमबाग ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।घटना की सूचना मिलते ही निगोहां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मृत्यु के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सके।

प्रयागराज अदालत का सांसद पप्पू यादव को तलब करने का आदेश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ प्रयागराज की अदालत ने साधु-संतों के वेश में कथित रूप से चंदा चोरी का प्रदर्शन करने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपों से जुड़े मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कक्ष संख्या-10) योगेश जैन की अदालत ने प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ मानते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पप्पू यादव को 11 अगस्त 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है।यह मामला भाजपा के विधि विभाग के प्रदेश सह-संयोजक एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्रा द्वारा दायर परिवाद पर आधारित है। शिकायतकर्ता ने अदालत में आरोप लगाया कि संसद भवन के सामने साधु का वेश धारण कर कथित रूप से मंदिर के दान पात्र से चंदा चोरी का अभिनय किया गया, जिससे सनातन धर्म, साधु-संतों, पुजारियों और हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। शिकायत में कहा गया कि इस प्रदर्शन के माध्यम से समाज में भ्रम और वैमनस्य फैलाने की कोशिश की गई।शिकायतकर्ता का कहना है कि अयोध्या स्थित राम मंदिर के दान पात्र से धनराशि चोरी की वास्तविक घटना को आधार बनाकर उसका कथित रूप से भ्रामक और कूटरचित प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कथित कृत्य के माध्यम से धार्मिक प्रतीकों और साधु-संतों की छवि को धूमिल करने तथा समाज में तनाव पैदा करने का प्रयास किया गया। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि पप्पू यादव के विरुद्ध पहले से विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज होने का दावा किया गया है।परिवाद पर सुनवाई के बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोपों का संज्ञान लेते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 196, 298, 299 और 356 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय ने पप्पू यादव को नोटिस जारी करते हुए 11 अगस्त 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी, जहां दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अदालत द्वारा मुकदमा दर्ज करने और समन जारी करने का अर्थ यह नहीं है कि आरोप सिद्ध हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल : 13 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले, कई मंडलायुक्त और विभागों को मिले नए मुखिया

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शासन और प्रशासन को अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 13 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत कई मंडलों के मंडलायुक्त बदले गए हैं, जबकि आवास, कृषि, गृह, विद्युत, श्रम, औद्योगिक विकास और दुग्ध विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी नई नियुक्तियां की गई हैं। सरकार ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।तबादला सूची के अनुसार गोरखपुर मंडलायुक्त अनिल ढींगड़ा को उनके वर्तमान दायित्व के साथ निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं इन्द्रविक्रम सिंह, जो सचिव कृषि, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग तथा निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के पद पर कार्यरत थे, उन्हें गोरखपुर का नया मंडलायुक्त बनाया गया है।प्रमुख सचिव कृषि रविन्द्र को आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निदेशक नगर भूमि सीमारोपण तथा सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का दायित्व सौंपा गया है। वहीं इन पदों पर कार्यरत डा. बलकार सिंह को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) नियुक्त किया गया है।पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक वैभव श्रीवास्तव को बस्ती मंडलायुक्त बनाया गया है। गृह एवं सतर्कता विभाग के सचिव श्रीप्रकाश बिन्दु को पीसीडीएफ का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।बरेली मंडलायुक्त भूपेन्द्र एस. चौधरी को सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शम्भू कुमार को बरेली मंडलायुक्त बनाया गया है।लोक निर्माण विभाग के सचिव डा. लोकेश एम. को प्रयागराज मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं प्रयागराज मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल को उत्तर प्रदेश का श्रमायुक्त बनाया गया है।राजस्व परिषद, प्रयागराज के सदस्य (न्यायिक) संदीप कुमार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।इसके अलावा गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव पुष्प राज सिंह को नोएडा का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल को विशेष सचिव, गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।सरकार के इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को शासन व्यवस्था में कार्यकुशलता बढ़ाने, विभागीय समन्वय मजबूत करने तथा विकास कार्यों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई तैनाती पाने वाले अधिकारियों के सामने अपने-अपने विभागों और क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकताओं को तेजी से लागू करने, जनसेवाओं में सुधार लाने तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होगी।प्रशासनिक हलकों में इस तबादला सूची को राज्य सरकार की बड़ी प्रशासनिक कवायद के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आगामी महीनों में विकास परियोजनाओं, शहरी नियोजन, कृषि सुधार, औद्योगिक निवेश, विद्युत व्यवस्था और कानून-व्यवस्था से जुड़े कार्यों में इन अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

रोवर तकनीक से भूमि सीमांकन का सफल प्रदर्शन, राजस्व मंत्री बोले— विवादों के समाधान में आएगी तेजी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि सीमांकन प्रक्रिया को अधिक सटीक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंगलवार को लखनऊ जिले की मोहनलालगंज तहसील के ग्राम करोरवा में आधुनिक जीएनएसएस रोवर तकनीक के माध्यम से भूमि सीमांकन का सफल प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजस्व राज्यमंत्री सुरेन्द्र सिंह दिलेर ने स्वयं सीमांकन प्रक्रिया का अवलोकन किया और इसे राजस्व प्रशासन के लिए एक क्रांतिकारी पहल बताया।कार्यक्रम में राजस्व परिषद के अधिकारी राजेश रंजन (आईएएस) की उपस्थिति में तहसील मोहनलालगंज की राजस्व टीम ने आधुनिक जीएनएसएस रोवर मशीन और पारंपरिक जरीब पद्धति, दोनों माध्यमों से भूमि का सीमांकन किया।

प्रदेश के 75 जिलों में आज होगा डेयरी कॉन्क्लेव, किसानों को मिलेंगी नई तकनीक और योजनाओं की जानकारी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। दुग्धशाला विकास विभाग के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर बुधवार, 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक दिवसीय जनपद स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव-2026 का आयोजन किया जाएगा। दुग्धशाला विकास विभाग और पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुग्ध उत्पादक किसानों, पशुपालकों और स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक डेयरी तकनीकों, वैज्ञानिक पशुपालन और विभागीय योजनाओं से जोड़ना है।पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम तथा दुग्ध आयुक्त के. धनलक्ष्मी के निर्देश पर आयोजित इस कॉन्क्लेव का मुख्यालय से वेब लिंक के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाएगा। जिला स्तर पर कार्यक्रम विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होगा, जबकि उद्घाटन जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा।कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों, दुग्ध संघों के प्रतिनिधियों, दुग्ध उत्पादक किसानों, पशुपालकों, स्वयं सहायता समूहों, दुग्ध समितियों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक मुख्यालय से विशेषज्ञों के व्याख्यान और तकनीकी सत्रों का सीधा प्रसारण किया जाएगा।कॉन्क्लेव में नन्द बाबा दुग्ध मिशन, दुग्ध नीति-2022, आधुनिक डेयरी प्रबंधन, दुग्ध प्रसंस्करण, हरे चारे का प्रबंधन, पशु रोगों की पहचान, रोकथाम, निगरानी, नियंत्रण, टीकाकरण तथा विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

आंदोलन पूरी तरह से छात्रों और युवाओं का

नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और सोनम वांगचुक की 26 दिन तक चली भूख हड़ताल की तुलना 2011 के अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से की जा रही है। ऊपर से देखने पर लगेगा कि वैसा ही आंदोलन है। इससे पहले हुए किसी दूसरे आंदोलन से भी इसकी तुलना की जा सकती है। कह सकते हैं कि छात्र और नौजवान वैसे ही उद्वेलित हुआ, जैसे 2012 में निर्भया कांड के समय था। ऊपरी तौर पर इसकी तुलना पिछले पांच दशक में हुए किसी भी दूसरे आंदोलन से की जा सकती है। जेपी के आंदोलन से भी तुलना कर सकते हैं तो मंडल, मंदिर, किसान, शाहीन बाग, पाटीदार या मराठा आंदोलन के कुछ कुछ तत्व इस आंदोलन में भी तलाशे जा सकते हैं। लेकिन थोड़ी बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा कि यह आंदोलन अब तक हुए सभी आंदोलनों से कई मायने में भिन्न है।

इस आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें किसी तरह की अस्मिता नहीं तलाश सकते हैं। इस लिहाज से यह जेपी और अन्ना हजारे के आंदोलन की तरह है। उन दोनों आंदोलनों में भी समाज का हर वर्ग शामिल था क्योंकि उनमें जिस चीज का विरोध किया जा रहा था वह हर वर्ग को प्रभावित करने वाली थी। बाकी आंदोलनों में किसी न किसी तरह की अस्मिता का मामला रहा है। मंडल से लेकर मराठा या पाटीदार आरक्षण के आंदोलन में जातीय अस्मिता प्रमुख थी। मंदिर आंदोलन में भी हिंदू अस्मिता बहुत मुखर थी तो शाहीन बाग में मुस्लिम अस्मिता। निर्भया कांड के समय हुआ आंदोलन एक फ्लैश प्रोटेस्ट था, जो एक घटना से उपजा था और जल्दी ही समाप्त हो गया। उसका दायरा पूरे देश में नहीं फैला था।

इन सबसे उलट नीट यूजी के पेपर लीक के खिलाफ चल रहा आंदोलन पूरी तरह से छात्रों और युवाओं का है। इसमें एक खास बात यह भी है कि कोई एक व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि वह आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। सोनम वांगचुक जरूर इस आंदोलन की नैतिक ताकत हैं लेकिन नेतृत्व उनके हाथ में भी नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी आंदोलन का नेतृत्व करने का दावा नहीं कर सकते हैं। ऐसे आंदोलन के अक्सर अराजक हो जाने का खतरा रहता है।

परंतु यह आंदोलन इतना लंबे चलने के बावजूद अराजक नहीं हुआ। जंतर मंतर पर मोटे तौर पर शांति बनी रही। दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में जरूर कुछ प्रदर्शनों में हिंसा होने की खबरें आईं लेकिन दिल्ली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बावजूद शांति रही। इसका कारण यह था कि आंदोलन में असली स्टेकहोल्डर्स शामिल थे। यानी ऐसे छात्र शामिल हुए, जिनको अपना भविष्य बचाना है। वे पेशेवर नेता या प्रदर्शनकारी नहीं थे। छात्र और युवा अपने वास्तविक सरोकारों की वजह से जंतर मंतर पर पहुंचे थे।

असल में शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था की गड़बड़ियों के खिलाफ गुस्सा काफी समय से जमा हो रहा था। यह सिर्फ अखिल भारतीय परीक्षाओं जैसे नीट यूजी या जेईई या सीयूईटी आदि का मामला नहीं है। दाखिले और नौकरी के लिए होने वाली राज्यों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी लगातार गड़बड़ी हो रही थी। छात्रों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि परीक्षाओं का कैलेंडर नहीं बना है। नियमित परीक्षाएं नहीं होती हैं।

कई साल की परीक्षाओं को मिला कर एक परीक्षा होती है और उसमें भी पेपर लीक हो जाता है या परीक्षा केंद्र मैनेज करके अलग तरह की धांधली होती है। अगर पेपर लीक या परीक्षा केंद्र मैनेज होने की घटना न हो तो प्रश्न पत्र में गड़बड़ी हो जाती है, उत्तर पुस्तिका जांचने में गड़बड़ी हो जाती है या नतीजे आने में बहुत समय लग जाता है। कई साल की परीक्षा एक साल कराने की वजह से बड़ी संख्या में छात्रों की उम्र सीमा पार हो जाती है। इन सबका संचित गुस्सा जंतर मंतर पर निकला है।

शिक्षा और परीक्षा की व्यवस्था में गड़बड़ियों से परेशान एक पूरी पीढ़ी ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। यह इसकी सबसे खास बात है। जिस पीढ़ी को 'जेन जी कहा जाता है और जिसमें 14 से लेकर 29 साल तक के युवा हैं, वह पीढ़ी इस आंदोलन में सड़कों पर उतरी। यह फीगर ऑफ स्पीच नहीं है कि ये आंदोलन 'जेन जी का। सचमुच आठवीं, नौवीं क्लास की लड़कियां, जिनकी उम्र 14 या 15 साल की है वो प्रदर्शन करने पहुंचीं। अपने क्लास की किताब लेकर लड़कियां आईं, जिन्होंने पढ़ कर सुनाया कि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है और आज वास्तव में क्या हो रहा है। वयस्क होने से पहले की उम्र के सैकड़ों छात्र और युवा जंतर मंतर पर दिखाई दिए, जिनके चेहरे पर दृढ़ प्रतिबद्धता थी। वे किसी राजनीतिक विचार से प्रभावित नहीं थे। उनको अपने भविष्य की चिंता थी। उनको लग रहा था कि ऐसे ही चलता रहा तो उनकी पढ़ाई और उनका परिश्रम व्यर्थ जाएगा।

आखिर क्यों पूरा नहीं कर पाते शिक्षा मंत्री अपना कार्यकाल

योगेंद्र योगी

मोदी सरकार के कार्यकाल के चारों शिक्षा मंत्रियों में से एक भी अपना विज़न लागू करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। रणनीतियां ऊपर से बनती थीं। ये ज़रूर है कि हर मंत्री का उसे लागू करने का तरीक़ा अलग हो सकता है जैसे, स्मृति ईरानी ज़्यादा मुखर थीं

कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और सरकार की प्राथमिकताओं पर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ़ इस्तीफा देने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पर नहीं, बल्कि मोदी सरकार के दौरान शिक्षा मंत्रालय की पूरी दिशा को लेकर भी उठ रहे हैं। साल 2014 से केंद्र में सत्ता में आने के बाद से अब तक मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री रही स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल 'निशंक' और धर्मेंद्र प्रधान को अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा।

पांचवा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को बनाया गया है, हालांकि जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मोदी सरकार को तय करना है कि जोशी ही पूर्णकालिक शिक्षा मंत्री रहेंगे या किसी नए चेहरे की तलाश करके उसको स्वतंत्र रूप से शिक्षा मंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जोशी भी विवादों में रहे हैं। साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो गैंग रेप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र क़ैद की सज़ा काट रहे 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई पर जब चौतरफ़ा सवाल उठ रहे थे, तब प्रल्हाद जोशी ने इसका बचाव किया था।

सवाल यही है कि आखिरकार कोई भी शिक्षा मंत्री अपना कार्यकाल क्यों नहीं पूरा कर पाया। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय ही ऐसा प्रमुख मंत्रालय रहा, जिसकी कमान पांच अलग-अलग मंत्रियों ने संभाली वहीं, गृह, विदेश, वित्त, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे मंत्रालयों में अपेक्षाकृत स्थिरता बनी रही। शिक्षा, संस्कृति और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (आईएनबी) ऐसे कुछ चुनिंदा मंत्रालय हैं, जिन्हें सॉफ्ट पावर की तरह देखा जाता है और जो संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अहम रहे हैं।

यही कारण है कि यहां विवाद ज़्यादा हुए और अस्थिरता भी उतनी ही दिखती है। गौरतलब है कि आईएनबी में 12 साल के भीतर सात केंद्रीय मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में पांच केंद्रीय मंत्री बने हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभाला मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह ज़िम्मेदारी रमेश पोखरियाल 'निशंक' को मिली। मगर 2021 में हुए कैबिनेट विस्तार के दौरान धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बना दिया गया, जिनके इस्तीफ़े की मांग को लेकर एक महीने तक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक जंतर-मंतर पर बैठे रहे और आख़िरकार केंद्र सरकार दबाव में आई और प्रधान को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा।

नीट परीक्षा के लीक होने का मामला अलग कर दें, तो संघ से जुड़े उन सभी प्रमुख लक्ष्यों को धर्मेंद्र प्रधान बिना शोर-शराबा किए लागू करा पाने में सफल रहे हैं, जिनकी कोशिश उनके पूर्ववर्तियों ने ज़ोर लगाते हुए की और विवादों में फंसते गए। ग़ौरतलब है कि 2014 में बनी पहली मोदी कैबिनेट में धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया, फिर मोदी के दूसरे कार्यकाल में वे शिक्षा मंत्री बने और मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी यह ज़िम्मेदारी जारी रही। प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को बढ़ावा मिला। मातृभाषा और कई भाषाओं में शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया। मगर तीन-भाषा फ़ॉर्मूला पर तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ लंबे समय तक वे विवाद के केंद्र में भी रहे। विरोधियों ने उन पर राजनीतिक हस्तक्षेप और हिंदी थोपने का आरोप लगाया, जिससे शिक्षा नीति केंद्र बनाम राज्य के विवाद का मुद्दा बन गई।

मोदी सरकार के कार्यकाल के चारों शिक्षा मंत्रियों में से एक भी अपना विज़न लागू करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। रणनीतियां ऊपर से बनती थीं। ये ज़रूर है कि हर मंत्री का उसे लागू करने का तरीक़ा अलग हो सकता है जैसे, स्मृति ईरानी ज़्यादा मुखर थीं, जावड़ेकर रणनीतिक चुप्पी वाले व्यक्ति थे। मोदी के शासन में शिक्षा विभाग में जो भी नीतियां अपनाई गईं, वे सभी वाम विचारधारा को हटाने के मक़सद से लागू हुईं। संघ का मक़सद भारत की शिक्षा व्यवस्था से वाम विचारधारा वाली शिक्षा-पद्धति को हटाना है, क्योंकि संघ मानता है कि वे मुग़लों के समर्थक रहे हैं। संघ की नज़र में, मुग़ल घुसपैठिए हैं और देश की मुस्लिम आबादी उनकी वंशज है। संघ पर आरोप लगते रहें कि इस एजेंडे को पूरा मोदी सरकार के जरिए कराया जा रहा है। इसी लक्ष्य को साधने के लिए मोदी सरकार के चार शिक्षा मंत्रियों के चयन का पैमाना रहा है। स्मृति ईरानी को छोड़ दें, तो नवनियुक्त शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल 'निशंक' और धर्मेंद्र प्रधान संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। वाजपेयी के ज़माने में भी संघ से आने वाले मुरली मनोहर जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, जो दर्शाता है कि संघ इस मंत्रालय में अपना दख़ल हमेशा चाहता रहा है। स्मृति ईरानी के साथ उनके नाम पर डिग्री विवाद, जेएनयू विवाद और रोहित वेमुला की आत्महत्या जैसे विवाद जुड़ चुके थे।

स्मृति ईरानी संघ की पृष्ठभूमि से नहीं थीं। नई शिक्षा नीति तैयार करने और उसे लागू करने में देरी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्मृति से बहुत खुश नहीं था। संघ के संदेशों को समझना आसान नहीं है। संघ शोर-शराबा नहीं करता। यही कारण है कि फिलाहल संघ की पृष्ठभमि वाले प्रकाश जोशी को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। मंत्रालय में स्मृति ईरानी के कार्यकाल के दौरान नई शिक्षा नीति पर काम की शुरुआत हुई। मोदी के कार्यकाल के तीसरे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' के समय इसे लागू किया गया।

शिक्षा मंत्री रहे रमेश निशंक की पहचान संघ से आने वाले एक विद्वान की रही है, जो संघ के मक़सद को आगे ले जा सकते थे। हालांकि, अपने अवैज्ञानिक बयानों को लेकर भी वे विवादों में आए। उन्होंने यहां तक कहा कि चरक ऋषि ने अणु-परमाणु की खोज की थी। कोविड के समय जेईई-नीट की परीक्षा कराए जाने की घोषणा के बाद निशंक के ख़िलाफ़ काफ़ी ऑनलाइन विरोध हुआ था। विरोध में लोग कोर्ट भी गए, जहां सरकार के पक्ष में फ़ैसला आया। हालांकि, तब बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने से रह गए, जिसे लेकर विवाद हुआ। उनके समय भी आरोप लगे कि नई शिक्षा नीति के ज़रिए केंद्र सरकार शिक्षा पर नियंत्रण अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है, जिसे उन्होंने नकार दिया था।

शिक्षा मंत्रालय के जरिए मोदी सरकार का सारा जोर संघ को साधने में रहा है, किन्तु शिक्षा के उत्थान के लिए बजट को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। इसी कारण शिक्षा मंत्रालय में बजट घटता गया और विवाद बढ़ते गए। केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय की हिस्सेदारी पिछले 12 वर्षों में तेज़ी से घटी है यह हिस्सा 2013-14 में कांग्रेस-नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 4.6% था, जो 2025-26 में घटकर 2.5% रह गया। शिक्षा का घटता बजट ही दर्शाता है कि मोदी सरकार शिक्षा में सुधार को लेकर गंभीर नहीं है। चारों शिक्षा मंत्रियों के समय में लगभग हर विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर फ़ैकल्टी के चयन में संघ की विचारधारा को प्राथमिकता दी गई है।

व्यंग्य

सरकार और भाजपा को हर मोर्चे पर मात

नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर हुए आंदोलन में सरकार और भाजपा को हर मोर्चे पर मात मिली। पिछले 12 साल में तैयार किया गया उसका कोई भी टूल इस बार काम नहीं आया। तमाम कोशिश के बावजूद सरकार, भाजपा और समर्पित मीडिया मिल कर इस आंदोलन को देशद्रोहियों का या भारत विरोधियों का या अमेरिका, चीन, पाकिस्तान प्रायोजित नहीं बता पाए। क्योंकि छात्रों और युवाओं के आक्रोश की वजहें इतनी ठोस थीं कि वे इस आंदोलन को सरकार विरोधी आंदोलन भी नहीं बता सके। इससे पहले हर आंदोलन में सरकार का अपना एक पक्ष होता था। जैसे किसान आंदोलन के समय भी सरकार का पक्ष था कि जो तीन केंद्रीय कानून बनाए गए हैं वो किसानों के भले के लिए हैं, उनके हित में हैं और देश के हित में भी हैं। लेकिन यह बात वे पेपर लीक के बारे में तो नहीं कह सकते थे कि पेपर लीक छात्रों और देश के हित में है। किसान आंदोलन के समय कहा जा रहा था कि सरकार किसानों के हित में कानून ले आई है लेकिन आढ़तिए या दूसरे हित समूह मिल कर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात छात्रों और युवाओं के आंदोलन में नहीं कही जा सकती थी। इसलिए पहले दिन से सरकार बैकफुट पर थी।

भाजपा, केंद्र सरकार के इकोसिस्टम और मीडिया ने किसानों के आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ दिया था, आंदोलनकारियों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहा जा रहा था, उनके आंदोलन में विदेशी हाथ बताया जा रहा था, अंतरराष्ट्रीय सिंगर रिहाना से लेकर युवा आंदोलनकारी ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि को भारत विरोधी टूलकिट का हिस्सा बताया जा रहा था। उससे पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ हुए प्रदर्शनों और विरोध को सरकार ने घुसपैठियों को बचाने की कवायद बता दिया था। सरकार ने अपने इकोसिस्टम के जरिए यह बात स्थापित कर दी थी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में हैं और मुस्लिम तुष्टिकरण व वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में कांग्रेस व दूसरी विपक्षी पार्टियां एसआईआर का विरोध कर रही हैं।

इसी तरह नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ शाहीन बाग से लेकर देश के दूसरे हिस्से में हुए आंदोलन को भी मुस्लिम तुष्टिकरण और पाकिस्तान, बांग्लादेश प्रायोजित आंदोलन बताया गया। रोहित वेमुला से लेकर जेएनयू तक में हुए प्रदर्शन से लेकर सीएए और कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन को सरकार ने बड़ी आसानी से टुकड़े टुकड़े गैंग का आंदोलन साबित कर दिया था। सरकार और भाजपा ने इन मामलों में जनमानस आंदोलनकारियों के खिलाफ बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी।

लेकिन पेपर लीक मामले में सरकार ऐसा नहीं कर पाई। इसका एक कारण तो यह था कि आंदोलनकारियों की एक ही अस्मिता थी वह थी 'जेन जीÓ की। हर जाति, धर्म, वर्ग और राज्य के युवा इसमें शामिल हुए। दूसरा कारण यह था कि प्रदर्शनकारियों के पास पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी का ठोस कारण था। तीसरा कारण यह था कि शुरुआत में तमाम राजनीतिक दल और पेशेवर प्रदर्शनकारी इससे दूर थे। चौथा कारण यह था कि आंदोलन योजनाबद्ध या प्रायोजित नहीं था।

इसलिए सरकार की ओर से इसकी साख बिगाड़ने की कोशिश हुई भी तो कामयाबी नहीं मिली। कई नेताओं ने बेशर्मी के साथ इसे विदेशी साजिश बताने का प्रयास किया। कहा गया कि अभिजीत दीपके अमेरिका से आए हैं और वे सीआईए के एजेंट हैं। यह भी कहा गया कि बड़ी साजिश के तहत 20 जुलाई की घटना हुई और उसका मकसद संसद पर हमला करना था ताकि नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाई जा सके।

लेकिन ऐसा कोई भी प्रयास कामयाब नहीं हुआ। छात्रों ने कोई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं की। छिटपुट पत्थरबाजी और सुरक्षाकर्मियों से धक्कामुक्की के अलावा कोई ऐसी घटना नहीं हुई, जिसे किसी बड़ी साजिश के साथ जोड़ा जा सके। जब सारे दांव फेल हुए तब आनन फानन में प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश जारी हुआ, नया बिल लाने की घोषणा हुई, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल समाप्त कराई गई, शिक्षा विभाग के अधिकारी बदले गए और कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बातचीत शुरू हुई। बिना किसी राजनीतिक प्रशिक्षण के छात्र व युवा आंदोलन के लिए उतरे थे और उन्होंने मोदी सरकार को मजबूर किया कि वह उनकी शर्तें मान कर बातचीत करे।

ब्लॉग

नीलेकणी के ऊपर परीक्षा प्रणाली में सुधार का जिम्मा

अजीत द्विवेदी

इंफोसिस के सह संस्थापक और भारत में आधार क्रांति के सूत्रधार नंदन नीलेकणी के ऊपर केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देने का जिम्मा सौंपा है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पूर्व प्रमुख एस सोमनाथ को भी इस उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी का सदस्य बनाया गया है। पता नहीं लोगों को याद हो कि न हो, दो साल पहले इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। जैसे 2026 में नीट यूजी पेपर लीक के बाद यह कमेटी बनी है वैसे ही 2024 में नीट यूजी पेपर लीक के बाद वह कमेटी बनी थी। राधाकृष्ण कमेटी ने एक सौ ज्यादा सिफारिशें की थीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी 27 सिफारिशें ऐसी हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। कुछ सिफारिशें आंशिक तौर पर मानी गईं और 57 सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार किया गया। लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? दो साल के बाद फिर पेपर लीक हो गया!

राधाकृष्ण कमेटी ने सिफारिश की थी नीट यूजी सहित करीब 20 प्रतियोगिता परीक्षाएं कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में विषय के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद भी पेपर लीक होना जारी है और दूसरी गड़बड़ियां भी हो ही रही हैं तो इसका अर्थ है कि एकमात्र समस्या यह नहीं है कि एनटीए में विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं। समस्या संरचनात्मक और व्यवस्थागत है। अगर नंदन नीलेकणी संरचनात्मक समस्याओं को समझ कर उसे ठीक करने का सुझाव देते हैं तब तो ठीक है अन्यथा इसका भी कोई मतलब नहीं होगा।

उनके सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती यह है कि क्या वे अखिल भारतीय परीक्षा के सिद्धांत को खत्म करने की सिफारिश करेंगे? क्या वे कहेंगे कि एक बार में 24 लाख छात्रों वाली नीट यूजी की परीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या वे यह सिफारिश कर सकते हैं कि मेडिकल में दाखिले की पुरानी व्यवस्था बहाल हो और नीट यूजी की बजाय राज्यों को अपने कॉलेजों में दाखिले का अधिकार पहले जैसा दिया जाए? यानी शिक्षा और परीक्षा के मामले में राज्यों की स्वायत्तता सुनिश्चित की जाए। अगर नंदन नीलेकणी की कमेटी नीट समाप्त करने और मेडिकल में दाखिले की परीक्षा का विकेंद्रीकरण करने की सिफारिश नहीं करती है तो उनकी सिफारिशों का स्कोप बहुत सीमित हो जाएगा और तब किसी बड़े सुधार की संभावना कम हो जाएगी।

अब सवाल है कि अगर नीट समाप्त करने या नीट जैसी दूसरी अखिल भारतीय परीक्षाएं खत्म करने की सिफारिश नीलेकणी कमेटी नहीं करती है तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? सबसे अच्छा तो यही होगा कि नीट को समाप्त किया जाए। लेकिन अगर सरकार की ओर से कमेटी की सिफारिशों का जो स्कोप तय किया जाएगा यानी जो फ्रेमवर्क दिया जाएगा उसमें पहले ही यह स्पष्ट कर दिया जाए कि नीट की परीक्षा जारी रहेगी तो फिर नीलेकणी कमेटी को नीट को इंजीनियरिंग में दाखिले की परीक्षा जेईई की तरह दो चरणों में कराने की सिफारिश करनी चाहिए। ध्यान रहे अगले साल नीट की परीक्षा जेईई की तरह कंप्यूटर आधारित होगी और कई पालियों में होगी। हालांकि उसमें प्रश्नपत्रों की कठिनता के आधार पर अंकों के सामान्यीकरण की अलग समस्या आती है। फिर भी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा पेपर लीक की संभावना को कम करती है। इसके साथ साथ अगर नीट की परीक्षा भी जेईई के तरह दो चरण में हो तो पेपर लीक की संभावना और कम हो सकती है। दो चरण का अर्थ है कि पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा हो और दूसरे चरण में एडवांस परीक्षा हो। पहले चरण में मल्टीपल च्वाइस वाले प्रश्न हों और दूसरे चरण में सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएं।

इसके अलावा नीलेकणी कमेटी को मेडिकल की पढ़ाई की फीस को नियमित करने के बारे में भी सुझाव देने चाहिए। अभी मेडिकल की परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न पत्र इसलिए लीक होते हैं कि एक बार में परीक्षा होती है और 720 अंकों की परीक्षा में अगर अच्छे अंक आ गए तो देश के प्रीमियम संस्थान में बहुत कम फीस में पढ़ने का मौका मिलता है। अन्यथा निजी कॉलेजों में फीस इतनी ज्यादा है कि लोग स्वाभाविक रूप से पेपर लीक पर पैसा खर्च करने के लिए प्रेरित होते हैं। खुद सरकार इसी वजह से इसे हाई स्टेक यानी बड़े दांव वाली परीक्षा मानती है। नीट के बचाव में तर्क दिया जाता है कि इसमें क्वालिफाई करके गरीब बच्चे भी मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। यह गलत है। निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस एक से डेढ़ करोड़ रुपए तक है। ऐसे में कौन गरीब अपने बच्चों को वहां पढ़ा पाएगा! अगर डोनेशन नहीं देना पड़े तब भी निजी कॉलेजों में मेडिकल की पढ़ाई का खर्च सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर है।

बहरहाल, नीलेकणी कमेटी को सिर्फ नीट पर विचार नहीं करना है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के सुझाव देने हैं। इसकी शुरुआत एनटीए से हो सकती है। भारत सरकार ने एक देश, एक परीक्षा की महत्वाकांक्षी योजना के तहत एनटीए का गठन किया। इसके बाद एक एक करके परीक्षाओं को अखिल भारतीय स्वरूप दिया जाने लगा। मेडिकल की परीक्षा के साथ साथ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए भी सीयूईटी की परीक्षा ली जाने लगी। इसमें अलग समस्याएं हैं। वास्तविकता यह है कि एनटीए देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में शून्य योगदान दे रहा है। सो, नीलेकणी कमेटी एनटीए को खत्म करने और पुरानी विकेंद्रित परीक्षा व्यवस्था बहाल करने की सिफारिश करे। सवाल है कि अगर एनटीए को समाप्त करना उसके स्कोप ऑफ वर्क से बाहर हो तो क्या करना चाहिए? तब उसे एनटीए में सुधार की सिफारिश करनी चाहिए।

सबसे पहला सुधार तो यह जरूरी है कि एनटीए को कम से कम वैधानिक दर्जा दिया जाए। अगर सरकार चाहती है कि यूपीएससी की तरह इसकी परीक्षाएं विश्वसनीय बनें तो इसे संवैधानिक नहीं तो वैधानिक दर्जा दिया जाए। इसका अपना कैडर बने ताकि तदर्थ ढंग से काम नहीं हो। अभी इधर उधर से ले आकर अधिकारियों को रखा जाता है और गड़बड़ी होने पर बाद में उनको वापस अपने कैडर में भेज दिया जाता है। इससे जवाबदेही नहीं बनती है। इसके बाद ठेके पर नियुक्ति रोकने की सिफारिश की जाए और परीक्षा से जुड़े काम आउटसोर्स करने पर रोक लगे। यूपीएससी की तरह एनटीए का अपना बुनियादी ढांचा बने। विशेषज्ञों की नियुक्ति हो और पूरे साल इसका काम चले। जैसे यूपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पत्र के ढेर सारे सेट बनते हैं और किसी को पता नहीं होता है कि परीक्षा में कौन से सेट का इस्तेमाल होगा वैसी व्यवस्था एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए भी की जाए। एनटीए जिन परीक्षाओं का आयोजन करता है उसके अलावा भी कई एजेंसियां हैं, जो दाखिला और भर्ती परीक्षा आयोजित करती हैं। उनमें भी एनटीए की तर्ज पर ही सुधार की सिफारिश होनी चाहिए। हालांकि सिर्फ कमेटी की सिफारिशों से कुछ खास नहीं होगा। सरकार की मंशा और राजनीतिक इच्छाशक्ति भी होनी चाहिए तभी जरूरी सुधार होंगे।

'मैं अकेली मर जाती, लेकिन मेरे प्रेमी को परिजन मार देते, इसलिए...', युवती ने नोट लिखकर युवक संग खाया जहर

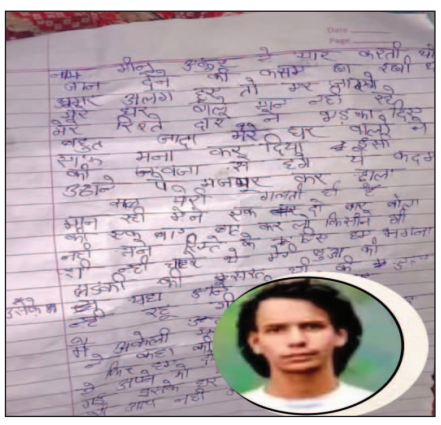

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

आगरा। सहारनपुर के चिलकाना के दुमझेड़ा गांव में प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। दोनों बेसुध हालत में गांव के बाहर खेत में पड़े मिले। इलाज के दौरान प्रेमी अंकुर (19) की मौत हो गई, जबकि प्रेमिका का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

नल्हेड़ा गांव निवासी अंकुर के परिवार की रिश्तेदारी दो किमी दूर नल्हेड़ा गांव में है। अंकुर और रिश्तेदार युवती के बीच काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे। इस संबंध में दोनों परिवारों के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन युवती के परिजन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए।

रविवार देर रात अंकुर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए दुमझेड़ा गांव में पहुंचा। रात करीब दो बजे अंकुर ने अपने एक परिचित को फोन किया और कहा कि उन्होंने दुमझेड़ा गांव के बाहर श्मशानघाट के पास जहरीला पदार्थ खा लिया।

पता चलते ही दोनों के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। वहां दोनों खेत में बेसुध हालत में पड़े थे। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानपुर ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर दोनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

युवती का इलाज जारी, हालत गंभीर

अंकुर की हालत बिगड़ती गई। उसे मेडिकल कॉलेज से चंडीगढ़ रेफर किया गया था, लेकिन परिजन उसे शहर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां सोमवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं, युवती का इलाज जारी है। उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है।

अकेली मर जाती, लेकिन मेरे प्रेमी को परिजन मार देते

प्रेमी युगल के पास एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें युवती ने लिखा कि हम प्रेम करते थे। हमने जान देने की कसमें खाई थीं। अगर अलग हुए तो मर जाएंगे। मेरे घर वाले मान नहीं रहे। उन्हें मेरे रिश्तेदारों ने भड़का दिया है। परिजनों ने शादी से साफ मना कर दिया। इसी वजह से हम यह कदम उठाने पर मजबूर किया। सारी गलती मेरी है। मैंने परिजनों से बोला कि एक बार बात कर लो। किसी ने भी रिश्ते के लिए नहीं सुनी। हम भागना नहीं चाहते थे। मैं अकेली मर जाती, लेकिन परिजन मेरे प्रेमी को मार देते। इसलिए एक साथ मरने का फैसला लिया।

पुलिस की प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि मौके से मिला सुसाइड नोट युवती ने लिखा है। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और बात शादी तक जा पहुंची।

चार भाइयों में दूसरे नंबर का था अंकुर

परिवार में अंकुर चार भाइयों में दूसरे नंबर का था। परिवार का खर्चा मजदूरी से चल रहा था। अंकुर भी मजदूरी करता था। अंकुर का एक बड़ा भाई है, जिसकी शादी हो चुकी है। दो छोटे भाई हैं। अंकुर की प्रेमिका बड़े भाई की रिश्तेदार है।

दोनों पक्षों की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके से सुसाइड नोट मिला है।- विकास प्रताप सिंह चौहान, सीओ सदर

पूर्व में हुई घटनाएं

दो जुलाई 2026 को कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र की स्टेट बैंक कॉलोनी में लैब टेक्नीशियन केरलम निवासी सैम कमनिश (40) और रसूलपुर पापड़ेकी निवासी शिक्षिका आस्था (23) का शव मिले थे। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के परिजन इसके खिलाफ थे।

21 जून 2026 देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव सुन्दलहेड़ी निवासी युवक अंकुश (20) व नागल क्षेत्र के गांव मडकी (गांगनौली) निवासी विवाहिता काजल (22) ने जहरीला पदार्थ का सेवन किया था। दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उनमें लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

17 अक्तूबर 2025 सरसावा के गांव सुआखेड़ी में गौरव (26) और उसकी प्रेमिका काजल (25) ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। दोनों रेलवे अंडरपास पर तड़पते हुए मिले थे। परिजन शादी कराने के लिए राजी नहीं थे।

21 मई 2023 में गंगोह के गांव मैनपुरा निवासी प्रेमी युगल आयशा (25 वर्ष) व मेहरदीन ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर जान दे दी थी। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

चेहल्लुम पर निकला दरिया वाला जुलूस

जौनपुर। शहर के मौला अलीघाट, मुफ्ती मोहल्ला में 20 सफर के अवसर पर आयोजित ऐतिहासिक दरिया वाला जुलूस मंगलवार को पूरी अकीदत, गम और शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ। बड़ी संख्या में मोमिनीन ने जुलूस में शिरकत कर हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए कर्बला को अश्कों के साथ खिराज-ए-अकीदत पेश किया। जुलूस से पूर्व आयोजित मजलिस का आगाज मरहूम नजर हसन एडवोकेट के हमनवा जनाब सैय्यद मेहदी जैदी की सोजखवानी से हुआ। इसके बाद हुज्जतुल इस्लाम मौलाना महफूजुल हसन खाँ ने मजलिस को खिताब करते हुए कर्बला के पैगाम, सब्र, इंसाफ और शोहदाए कर्बला की अजीम कुर्बानियों पर से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन का गम केवल शिया समुदाय तक सीमित नहीं, बल्कि हर इंसानियत पसंद, न्यायप्रिय और सत्य का साथ देने वाले व्यक्ति का गम है। उन्होंने कहा कि कर्बला का पैगाम मजहबी सीमाओं से ऊपर उठकर इंसानियत, अमन, भाईचारे, इंसाफ, सब्र और जुल्म के ख़िलाफ डटकर खड़े होने की सीख देता है।

युवक पर हुए गोलीकांड में 04 नामजद के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

- कुड़वार थाना क्षेत्र के महारागंज अझूई मार्ग पर रविवार देर रात हुई थी वारदात
- पुराने मुकदमे में सुलह न करने पर जानलेवा हमले का आरोप

आर्यावर्त संवाददाता

कुड़वार/सुल्तानपुर। रविवार रात करीब साढ़े दस बजे अझूई से घर जा रहे युवक को गोली मारकर लहूलुहान करने के मामले में पुलिस ने घायल युवक के भाई की तहरीर पर चार नामजद लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

बता दे कि रविवार को बंधुआ कला थाना क्षेत्र अतागंज गांव निवासी मिर्जा सफीर बेग पुत्र कयूम बेग अपनी कार से अझूई से घर जा रहे थे। रास्ते में रैपुरवा महराजगंज मार्ग पर पानी की टंकी के पास बाइक सवार लोगों ने गोली मारकर लहूलुहान कर दिया था। पुलिस को घायल युवक के भाई मिर्जा आमिर बेग ने सोमवार को तहरीर देकर आरोप लगाया कि अझूई गांव निवासी महमूद, तौहीद, फातिमा व समीरूल से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। जिसमे विगत वर्ष 2025 में एसपी के आदेश पर जालसाजी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में सुलह करने के लिए महमूद, तौहीद, अरशद व सोहेल द्वारा पूर्व में घायल युवक पर दबाव बनाया जा रहा था। जब उसने सुलह नहीं किया तो इन लोगो ने रविवार रात गोली मारकर सफीर बेग को घायल कर दिया। गोली सफीर के पेट में लगी है। जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर महमूद,तौहीद, अरसद व सोहेल के खिलाफ जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।थाना प्रभारी प्रवीण कुमार यादव ने मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि की है।

तेज बारिश ने गर्मी से पहुंचाई राहत, जलभराव

जौनपुर। कई दिनों से पड़ रही भीषण उमस और गर्मी से सोमवार देर रात लोगों को राहत मिली। रात करीब 11 बजे अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज बारिश शुरू हो गई। करीब एक घंटे तक हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश ने नगर पालिका परिषद की तैयारियों की पोल भी खोल दी। शहर के कई प्रमुख मार्गों और निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद कई स्थानों पर सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं। जगह-जगह बने गड्ढों में दोपहिया और चारपहिया वाहन फंसते रहे, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। प्रशासन और नगर पालिका की ओर से सड़कों को गड्ढामुक्त करने और जलनिकासी व्यवस्था बेहतर करने के दावों के बावजूद जमीनी हकीकत अलग दिखाई दी।

मां की लाश पर बैठा 'काल', बेटी के सामने महिला को जिंदा चबा गया तेंदुआ

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में ठाकुरद्वारा इलाके के लालापुर पीपलसाना गांव में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में खौफ फैला दिया है। अपने खेत में पशुओं के लिए गन्ने की पत्तियां उतारने गईं 45 वर्षीय संतोष देवी पर गन्ने के झुरमुट में छिपे खूंखार तेंदुए ने अचानक पीछे से जानलेवा हमला कर दिया। तेंदुए का हमला इतना भयानक था कि उसने महिला का सिर, चेहरा और सीने का हिस्सा बुरी तरह नोच डाला, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

मौत का यह खौफनाक मंजर तब सामने आया, जब काफी देर तक घर न लौटने पर संतोष देवी की बेटी रश्मि खेत पहुंची। वहां अपनी मां के क्षत-विक्षत शव के पास तेंदुए को बैठा देख उसकी चीख निकल गई। बेटी के शोर मचाते ही आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण दौड़ पड़े, जिन्हें देखकर तेंदुआ जंगल की ओर भाग निकला। इस हृदयविदारक घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और करीब दो घंटे तक शव को पिकअप में नहीं उठाने दिया। गुस्साए लोग पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देने और तेंदुए को तुरंत पकड़ने की मांग कर रहे थे। महिला की मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत और आश्वासन के बाद स्थिति को संभाला।

लालापुर पीपलसाना निवासी वीरेंद्र सिंह सैनी की पत्नी संतोष देवी रोज की तरह खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गई थीं। गन्ने के घने खेत में काम करते समय घात लगाए बैठे तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। काफी देर तक घर वापस न लौटने पर उनकी बेटी उन्हें ढूंढते हुए खेत पहुंची। वहां का खौफनाक दृश्य देखकर वह बदहवास होकर चिल्लाने लगी। ग्रामीणों ने एकजुट होकर तेंदुए को घेरने की कोशिश की, लेकिन वह चकमा देकर भाग निकला। इस भयावह घटना ने पूरे गांव को गहरे सदमे और दहशत में डाल दिया।

ग्रामीणों का भारी आक्रोश

तेंदुए के हमले में महिला की मौत की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वन विभाग की कथित लापरवाही से नाराज लोगों ने पुलिस को शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से रोक दिया। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में तेंदुए की आवाजाही की शिकायतें पहले भी की गई थीं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जब पुलिस शव को पिकअप में रखकर गांव से ले जाने लगी तो ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया। करीब दो घंटे तक चले हंगामे के कारण पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना रहा।

प्रशासन ने क्या कहा?

हालात बिगड़ते देख एसडीएम अभिषेक कुमार सिंह और एसपी ग्रामीण कुमार आकाश सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों को समझाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने और तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमों को तैनात करने का भरोसा दिया। एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। फिलहाल वन विभाग इलाके में लगातार गश्त कर रहा है और लोगों को अकेले खेतों में न जाने की सलाह दी जा रही है।

भाई की हत्या के बाद चैकी बनाने की मांग उठाई

जौनपुर। कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को दूल्हे आजाद बिंद की बहन सौम्या बिंद ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने तरसांवा मोड़ पर एक स्थायी पुलिस चैकी स्थापित करने की मांग की। सौम्या बिंद ने अधिकारियों को बताया कि क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। तरसावा मोड़ पर पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है, जहां बिना किसी भूमि विवाद के पुलिस चैकी का निर्माण किया जा सकता है। यह स्थान पुलिस चैकी के लिए अत्यंत उपयुक्त है और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायक होगा। वर्तमान में, गांव से संबंधित थाना लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

मुख्तार के शूटर अंगद की कहानी, जिसका निशाना अचूक, 25 केस... 2 बोतल शराब के साथ बिहार में खुद को क्यों कराया था अरेस्ट

आर्यावर्त संवाददाता

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को पुलिस और जिला प्रशासन ने गैंग के मुख्य शार्प शूटर माने जाने वाले अंगद राय उर्फ झूलन की करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर ली। पुलिस का दावा है कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी और इसे आरोपी ने अपनी पत्नी के नाम पर कराया था। प्रशासन ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत यह कार्रवाई की।

पुलिस के मुताबिक अंगद राय ने अपराध से अर्जित धन के जरिए मुहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के गिरधरिया गांव में जमीन और मकान

खरीदा था। यह संपत्ति उसकी पत्नी सरिता राय के नाम पर दर्ज है। प्रशासन के अनुसार, व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित इस संपत्ति की मौजूदा बाजार कीमत करीब 9।5 करोड़ रुपये आंकी गई है। जिलाधिकारी के आदेश और पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद कुर्की की कार्रवाई पूरी की गई।

अंगद राय उर्फ झूलन को लंबे समय तक मुख्तार अंसारी गैंग का सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर माना जाता रहा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, धमकी, गैंगस्टर एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में करीब 25 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अपराध की दुनिया में उसका नाम एक ऐसे शूटर के रूप में लिया जाता रहा, जिसका निशाना बेहद सटीक माना जाता था। यही वजह थी कि वह गैंग के सबसे अहम सदस्यों में गिना जाता था।

गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनाया था अनोखा तरीका

अंगद राय का नाम वर्ष 2023 में उस समय भी चर्चा में आया था, जब उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक अनोखी चाल चली। पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बिहार पहुंच गया, जहां शराबबंदी लागू है। दुर्गावती थाना क्षेत्र के नुआंव गांव के पास वह कथित तौर पर दो बोतल शराब और दो बीयर कैन के साथ पकड़ा गया। माना गया कि उसने जानबूझकर खुद को बिहार पुलिस के हाथों गिरफ्तार कराया, ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस की तत्काल गिरफ्तारी से बच सके।

आजीवन कारावास की सजा भी पा चुका

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अंगद राय एक हत्या के मामले में निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा भी पा चुका है। हालांकि बाद में उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। जेल से बाहर आने के बाद भी उस पर गवाहों को धमकाने के आरोप लगे। पुलिस के अनुसार, अंगद राय, उसके भाई विश्वनाथ राय और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ गाजीपुर के पप्पू गिरी को कोर्ट में गवाही न देने के लिए धमकाने का मामला भी दर्ज हुआ था।

अपराध के दम पर बनाया राजनीतिक प्रभाव

अंगद राय का प्रभाव केवल अपराध तक सीमित नहीं रहा। पुलिस के अनुसार, उसने अपने प्रभाव के चलते अपनी पत्नी सरिता राय को भांवरकोल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी जिताया था। इससे इलाके में उसकी राजनीतिक पकड़ की भी चर्चा होती रही।

अवैध संपत्तियों पर जारी रहेगा अभियान

गाजीपुर पुलिस का कहना है कि माफिया और गैंगस्टर नेटवर्क की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन का मानना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त करना संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस ने साफ किया है कि मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े अन्य आरोपियों की संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जा रही है।

संक्षेप

जल निगम का पानी न आने का विरोध प्रदर्शन'

जौनपुर। मड़ियाहूं तहसील क्षेत्र के रामपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में जल संकट के चलते मंगलवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 4 दिनों से जल निगम का पानी न आने से परेशान 20 से 25 घरों के लोगों ने हाथ उठाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। 4 दिनों से पानी न आने के कारण लोग इधर-उधर से मांगकर किसी तरह गुजारा करने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि नाली जाम होने के कारण घरों के शौचालय का पानी भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसी गंदगी में गिरकर एक युवक मोहम्मद का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। लोगों का कहना है नाली की खुदाई के दौरान जल निगम की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद से पानी की आपूर्ति बाधित है ।ग्रामीणों ने नगर पंचायत चेयरमैन विनोद जायसवाल से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द पानी और नाली की समस्या का समाधान करने की मांग की है। आलमगीर, टींकू गुप्ता, रवि सोनकर, दिलबहार, काजू गुप्ता, नवसाद, राजन, साजन गुप्ता, तिवारी पान वाले आदि उपस्थित रहे।

जहरीला पदार्थ खाये प्रेमी युगल ने दम तोड़ा

जौनपुर। सरपतहा थाना क्षेत्र के कुसियाबहार गांव में सोमवार को शादी की जिद पर जहरीला पदार्थ खाने वाले प्रेमी युगल की उपचार के दौरान मौत हो गई। अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जहां मृतका के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया, वहीं दूसरी ओर बगैर पोस्टमार्टम कराए ही मृतक का दाह संस्कार कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। कुसियाबहार गांव निवासी उन्नीस वर्षीय संध्या पुत्री रामभवन के घर पर सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के मझलीपट्टी गांव निवासी प्रेमी सूरज पुत्र घूरेराम पहुंचा और शादी की बात करने लगा। परिजनों के विरोध के बाद मामला बिगड़ता देख दोनों ने एक साथ जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर दोनों को एंबुलेंस से स्थानीय सीएचसी लाया गया। वहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में सोमवार देर शाम संध्या की मौत हो गई। वहीं वाराणसी रेफर किए गए सूरज ने भी देर रात दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची सरपतहा पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस चैकी के निकट मिली युवक की लाष

जौनपुर। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ओलंदगंज सरायपोख्ता पुलिस चैकी से चंद कदम की दूरी पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली। बताते है कि घटना मंगलवार तड़के जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलें तो देखा चैराहे के पास स्थित मंदिर की नाली में औंधे मुंह मृत अवस्था में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष आंकी गई है। देखते ही देखते राहगीरों की अच्छी खासी भीड़ एकत्रित हो गई। कुछ ही देर में बगल में रहे पुलिस चैकी के जवान भी पहुंच गयें ।पुलिस ने लाश को नाले से बाहर निकाल कर काफी देर तक पहचान कराने का प्रयास किया लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी।

अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट में तेजी लायें

जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आधार नामांकन एवं अद्यतन कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में आधार सेवाओं की प्रगति, 0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार नामांकन, 5-7 वर्ष एवं 15-17 वर्ष आयु वर्ग के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट, लंबित प्रकरणों तथा आधार केंद्रों के संचालन की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि आधार नामांकन एवं अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के कार्य में तेजी लाई जाए तथा प्रत्येक पात्र नागरिक को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण आधार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर बल दिया।

आठ किलो देसी घी और 126.50 रुपये की लूट, 41 साल बाद मिली बेगुनाही; कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, दिया ये तर्क

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिनाख्त परेड में हुई लंबी देरी की ठोस वजह नहीं बता सकना अभियोजन की बड़ी विफलता है। आरोपी इससे उपजे संदेह का लाभपाने का अधिकारी होता है।

इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति संतोष राय की अदालत ने बदायूं में 41 साल पहले आठ किलो देसी घी और सवा सौ रुपये की लूट में सजा पाए कन्हई और कल्लू को बेगुनाह बताते हुए बरी कर दिया।

जबकि, सह-आरोपी हरपाल और दलचंद की अपील लंबित रहने के दौरान मौत हो जाने के कारण उनकी अपील पहले ही उपशमित हो चुकी है। इन्हें बदायूं की विशेष अदालत ने 15 मई 1987 को पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी।

मामला बदायूं जिले के बिसौली थाना क्षेत्र का है। 21 फरवरी 1985 को राधेश्याम शर्मा ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि वह साइकिल से बिसाउली से अपने गांव पालिया जा रहे थे। कोट और बिसाउली के बीच सड़क किनारे चार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया।

उन्होंने चाकू उनकी छाती पर रखकर उनसे चार किलो देसी घी के दो डिब्बे और 126.50 रुपये और कुछ किराने का सामान लूट लिया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल भेजने के 42 दिन बाद शिनाख्त परेड कराई।

इसके बाद कन्हई, कल्लू, हरपाल और दलचंद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। 1987 में ट्रायल कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुना दी। इसके खिलाफ चारों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। कोर्ट ने पाया कि आरोपियों की शिनाख्त परेड जेल भेजे जाने के लगभग 42 दिन बाद और घटना के ढाई महीने बाद कराई गई थी।

शिनाख्त परेड में देरी की वजह नहीं बताना अभियोजन की विफलता: कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिनाख्त परेड में हुई लंबी देरी की ठोस वजह नहीं बता सकना अभियोजन की बड़ी विफलता है। आरोपी इससे उपजे संदेह का लाभ पाने का अधिकारी होता है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति संतोष राय की अदालत ने बदायूं में 41 साल पहले आठ किलो देसी घी और सवा सौ रुपये की लूट में सजा पाए कन्हई और कल्लू को बेगुनाह बताते हुए बरी कर दिया।

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पर प्रतिबंध लगाने से हाईकोर्ट का इन्कार

वहीं, एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) पर प्रतिबंध लगाने, लगाने, उसकी संपत्तियों के हस्तांतरण, सीबीआई जांच और बीसीसीआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता और करीब दो दशक पुराने घटनाक्रम को इस स्तर पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से दायर याचिका पर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि वर्ष 1955 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत गठित पुरानी द उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का विधिसम्मत तरीके से विघटन नहीं किया गया।

भाजपा नेता पर पोस्ट के मामले में निलंबित शिक्षक बहाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक प्रदीप प्रताप सिंह के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने दिया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष के कथित गलत कार्यों पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में याची शिक्षक को निलंबित किया गया था।

याची शिक्षक ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि किसी गलत कार्य, गबन या जनहित से जुड़े मामले को उजागर करना मात्र कदाचार नहीं माना जा सकता, जब तक कि वह कानून या संबंधित सेवा नियमों का उल्लंघन न करता हो। कोर्ट ने शिक्षक की याचिका स्वीकार करते हुए फिरोजाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के 4 जुलाई 2026 को जारी निलंबन आदेश रद्द कर दिया।

दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये आदतें, दिल रहेगा फिट

आजकल दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए रोज की कुछ अच्छी आदतें अपनाना जरूरी है। आइए जानते हैं।

दिल हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है। यह पूरे शरीर में खून और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, जिससे शरीर के सभी अंग ठीक तरह से काम कर पाते हैं। आज के समय में दिल से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। कई लोग दिल की सेहत पर तब ध्यान देते हैं, जब कोई परेशानी शुरू हो जाती है। समय रहते दिल की देखभाल करने से भविष्य में कई परेशानियों का खतरा कम किया जा सकता है।

दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए रोज की कुछ अच्छी आदतें अपनाना जरूरी है। छोटी-छोटी अच्छी आदतें भविष्य में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा कम करने में मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं दिल को स्वस्थ रखने के लिए कौन-सी आदतें अपनानी चाहिए, किन आदतों से बचना चाहिए और किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

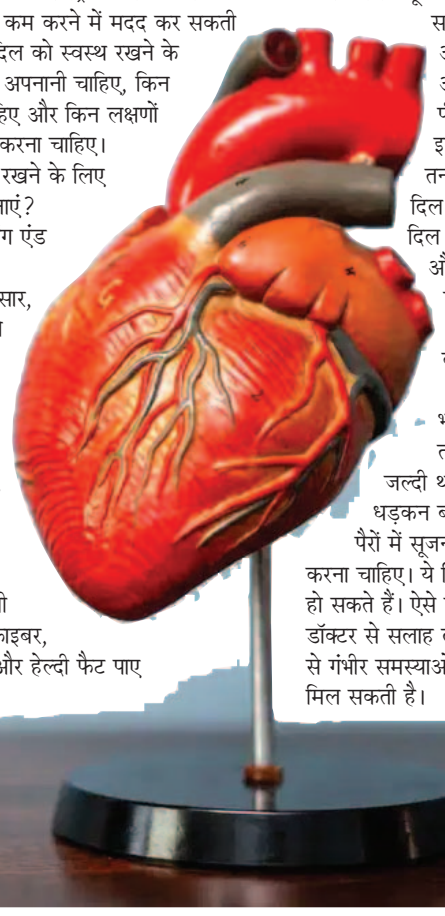

दिल को स्वस्थ रखने के लिए कौन-सी आदतें अपनाएं?

नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट (NHLBI) के अनुसार, दिल को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित खानपान और अच्छी लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी है। अपनी डाइट में फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, बीन्स, मेवे, बीज, कम फैट वाला दूध और मछली शामिल करें। इनमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट पाए जाते हैं, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। इसके साथ रोज शारीरिक एक्टिविटी करें, पर्याप्त नींद लें और अपने वजन को संतुलित रखने की कोशिश करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज है, तो उसे कंट्रोल में रखना भी जरूरी है। समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराना भी फायदेमंद हो सकता है। ये छोटी-छोटी आदतें लंबे समय तक दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं।

दिल को स्वस्थ रखने के लिए किन आदतों से बचें?

दिल की अच्छी सेहत के लिए धूम्रपान और तंबाकू से दूरी बनाकर रखें। बहुत ज्यादा नमक, चीनी, तले-भुने और प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन करने से बचें। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने की आदत भी दिल की सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अगर शराब पीते हैं, तो इसकी मात्रा सीमित रखें या इससे बचें। इसके अलावा, लगातार तनाव लेना और पूरी नींद न लेना भी दिल पर असर डाल सकता है। स्वस्थ दिल के लिए अच्छी लाइफस्टाइल अपनाना और रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देना जरूरी है।

किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

अगर सीने में दर्द, दबाव या भारीपन महसूस हो, सांस लेने में तकलीफ हो, बिना ज्यादा मेहनत के जल्दी थकान होने लगे, चक्कर आए, दिल की धड़कन बहुत तेज या अनियमित महसूस हो या पैरों में सूजन दिखाई दे, तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये दिल से जुड़ी किसी समस्या के संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह लें। समय पर जांच और इलाज कराने से गंभीर समस्याओं के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है।

कार के पिछले दरवाजे में छिपा है 'चाइल्ड लॉक' बटन, जानें बच्चों के सफर में क्यों है यह जीवनरक्षक

कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने परिवार के साथ कार से सफर कर रहे होते हैं, और पीछे की सीट पर बैठे बच्चे अनजाने में दरवाजा खोल देते हैं। ऐसे में गंभीर हादसे का खतरा काफी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप कार के 'चाइल्ड लॉक सेफ्टी' फीचर को एक्टिव रखते हैं, तो ऐसी घटनाओं का जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है। आइए, इस लेख में इसके बारे में विस्तार से समझते हैं।

परिवार के साथ कार में सफर करने का आनंद ही कुछ और होता है, लेकिन जब गाड़ी की पीछे की सीट पर छोटे बच्चे बैठे हों, तो अक्सर माता-पिता की चिंता काफी बढ़ जाती है कि कहीं बच्चे गलती से डोर न खोल दें। चंचल स्वभाव के कारण बच्चे अक्सर चलती गाड़ी में दरवाजों के लॉक या इनसाइड हैंडल से खेलने लगते हैं। अगर चलती कार का दरवाजा अचानक खुल जाए, तो पलक झपकते ही एक बेहद खौफनाक और जानलेवा हादसा हो सकता है।

इसी बड़े खतरे से निपटने के लिए हर आधुनिक कार के पिछले दरवाजों में एक छोटा सा 'चाइल्ड लॉक' बटन दिया जाता है। एक आम इंसान अक्सर इस सुरक्षा फीचर को देखना भूल जाता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि यह छोटा सा बटन बच्चों के लिए कैसे एक बड़ा जीवनरक्षक साबित होता है।

अंदर से दरवाजा खुलने के खतरा कम हो जाता है

कार का चाइल्ड लॉक एक छोटा सा मैकेनिकल स्विच होता है जो पिछले दरवाजों के अंदरूनी किनारे पर लगा होता है।

इसे एक्टिवेट करने के बाद अंदर बैठा बच्चा अगर गलती से डोर हैंडल को खींच भी दे, तो भी कार का दरवाजा भीतर से बिल्कुल नहीं खुलता।

इससे बच्चे चलती गाड़ी में अनजाने हादसों से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।

आपातकाल में बाहर से दरवाजा खोलना होता है बेहद आसान

कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि चाइल्ड लॉक ऑन करने से दरवाजा हमेशा के लिए जाम हो जाता है।

असल में यह फीचर सिर्फ अंदर के हैंडल को बेअसर करता है।

सफर पूरा होने के बाद गाड़ी रुकते ही बाहर खड़ा कोई भी व्यक्ति बाहर वाले मुख्य हैंडल को खींचकर दरवाजे को बेहद आसानी से खोल सकता है।

ऐसे करें एक्टिव

इस जीवनरक्षक फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है।

बस कार का पिछला दरवाजा खोलें, उसके किनारे पर दिए छोटे स्विच को अपनी उंगली या कार की चाबी से नीचे (On की तरफ) खिसका दें।

सफर के दौरान माता-पिता को मिलती है मानसिक शांति

जब कार के दोनों पिछले दरवाजों का चाइल्ड लॉक ऑन रहता है, तो ड्राइविंग कर रहे व्यक्ति या आगे बैठे माता-पिता को बार-बार पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती।

यह छोटा सा सुरक्षा कवच पूरे परिवार को बिना किसी डर और मानसिक तनाव के यात्रा का आनंद देता है और माता-पिता का पूरा ध्यान सुरक्षित ड्राइविंग पर रहता है।

क्या कम ब्लड प्रेशर से चक्कर आने पर कॉफी पीना सही है?

कम ब्लड प्रेशर एक ऐसी स्थिति है, जिसमें रक्तचाप सामान्य से कम होता है। इसे हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। इससे चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई लोग मानते हैं कि कॉफी पीने से रक्तचाप बढ़ता है और इससे चक्कर कम हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या वाकई कॉफी पीने से कम ब्लड प्रेशर के कारण चक्कर आने की समस्या ठीक हो सकते हैं या नहीं।

कॉफी में मौजूद कैफीन का असर

कॉफी में मौजूद कैफीन एक तरह का उत्तेजक होता है, जो थोड़े समय के लिए रक्तचाप को बढ़ा सकता है।

यह सच है कि कुछ समय के लिए कॉफी पीने से आपका रक्तचाप थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन यह असर बहुत ही अस्थायी होता है।

इसके बाद आपका रक्तचाप फिर से सामान्य हो जाता है। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि कॉफी हमेशा के लिए आपका रक्तचाप स्थायी रूप से बढ़ा देती है।

सेहत पर पड़ सकता है असर

कॉफी का ज्यादा सेवन सेहत पर असर डाल सकता है। इससे नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है और पेट में जलन हो सकती है।

इसलिए, कम ब्लड प्रेशर वाले लोगों को सीमित मात्रा में ही कॉफी का सेवन करना चाहिए। अगर आपको नियमित रूप से चक्कर आते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें और सही उपचार करवाएं।

कॉफी का सेवन सिर्फ थोड़ी देर के लिए राहत दे सकता है।

संतुलित डाइट का महत्व

कम ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए संतुलित डाइट लेना जरूरी है। हरी सब्जियां, फल, मेवे और प्रोटीन युक्त खाने की चीजें आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं।

ये पोषक तत्व आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं और रक्तचाप को स्थिर रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा पानी पीना भी जरूरी है, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और थकान और चक्कर जैसी समस्याओं से बचा जा सके।

संतुलित डाइट से आपकी सेहत अच्छी बनी रहती है।

अन्य उपाय

अगर आपको कम ब्लड प्रेशर की समस्या अक्सर होती है तो आपको केवल कॉफी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बेहतर यही होगा कि आप डॉक्टर से परामर्श करें और उनकी बताई डाइट लें, दवाइयां खाएं और सलाह का पालन करें।

इसके अलावा आप ज्यादा कम ब्लड प्रेशर महसूस होने पर तुरंत नमक और चीनी का घोल बनाकर पी सकते हैं या कुछ नमक वाला स्नैक खा सकते हैं।

कॉफी इसका इलाज नहीं है, लेकिन कुछ आराम दे सकती है।

कैंसर के इलाज में क्यों झड़ने लगते हैं बाल? एक्सपर्ट से जानें जरूरी बातें

कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर का इलाज करने के बाद बाल झड़ने लगते हैं। अधिकतर लोग इसका साइंटिफिटक कारण नहीं जानते हैं। चलिए आपको एक्सपर्ट के जरिए बताते हैं

कैंसर ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें अधिकतर लोगों की जान चली जाती है। इसलिए इस बीमारी का नाम सुनते ही लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर साल लाखों लोग अलग-अलग तरह के कैंसर की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। वैसे मेडिकल क्षेत्र में डेवलपमेंट की वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट काफी आसान हो गया है। इसके इलाज में की जाने वाली कीमोथेरेपी का एक साइड इफेक्ट बालों का झड़ना भी है।

लोग ये तो जानते हैं कि कैंसर के इलाज में बाल तेजी से झड़ते हैं और उनमें ये शिकायत भी रहती है कि बाल क्यों तेजी से गिर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है ये बहुत कम जानते हैं। एक्सपर्ट से जानें...

कैंसर में क्यों झड़ने लगते हैं बाल?

डॉ। जे।बी। शर्मा (डायरेक्टर, एक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड इम्यूनोथेरेपी, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल, दिल्ली) का कहना है कि कीमोथेरेपी का मकसद कैंसर सेल्स को खत्म करना होता है, लेकिन इसके साथ शरीर की कुछ हेल्दी सेल्स भी प्रभावित हो सकती हैं। हमारे हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ें बहुत तेजी से ग्रो करने वाली सेल्स से बनी होती हैं, इसलिए कीमोथेरेपी के दौरान बाल झड़ना एक कॉमन साइड इफेक्ट है।

आमतौर पर ट्रीटमेंट शुरू होने के 2 से 3 हफ्ते बाद हेयर फॉल शुरू हो सकता है। कुछ मरीजों में सिर्फ सिर के बाल, जबकि कुछ में आईब्रो, आईलैश और शरीर के अन्य हिस्सों के बाल भी झड़ सकते हैं। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में यह अस्थायी होता है।

फिर उगने लगते हैं बाल?

कीमोथेरेपी पूरी होने के कुछ हफ्तों या महीनों बाद बाल दोबारा उगने लगते हैं, हालांकि शुरुआत में उनका रंग या टेक्सचर थोड़ा अलग हो सकता है। यह भी जरूरी नहीं कि हर कीमोथेरेपी दवा से बाल झड़ेया हर मरीज में एक जैसा असर हो।

इन बातों का रखें ध्यान

इसलिए मरीजों को किसी भी तरह की चिंता होने पर अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से खुलकर बात करनी चाहिए। ट्रीटमेंट के दौरान माइल्ड शैंपू का इस्तेमाल, स्कैल्प की सही देखभाल, हेल्दी डाइट और पर्याप्त न्यूट्रिशन लेने से काफी मदद मिलती है। सबसे जरूरी बात यह है कि बाल दोबारा आ सकते हैं, लेकिन कैंसर का सही समय पर और पूरा इलाज मरीज की जिंदगी बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।

ITC Share Price: 4% की तेजी से निवेशकों के खिले चेहरे, क्या अब भी है कमाई का मौका?

सिगरेट पर टैक्स बढ़ने के झटके से उबरते हुए ITC के शेयर में करीब 4% की शानदार तेजी आई है। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा के स्टॉक को अपग्रेड करने और नया टारगेट देने से निवेशकों का भरोसा फिर लौट आया है।

शेयर बाजार में आईटीसी (ITC) के निवेशकों के लिए सोमवार, 3 अगस्त का दिन एक बड़ी राहत लेकर आया। टैक्स बढ़ोतरी के झटके से कंपनी का सिगरेट कारोबार तेजी से उबरता हुआ दिख रहा है और इसका सीधा असर स्टॉक पर पड़ा है। ट्रेडिंग सेशन के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर यह एफएमसीजी शेयर करीब 3।81 फीसदी की छलांग लगाते हुए 292।55 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पिछले सप्ताह शुक्रवार को यह शेयर 281 रुपये पर बंद हुआ था। सोमवार को 284।45 रुपये पर खुलने के बाद इसने जो रफ्तार पकड़ी, उसके पीछे दिग्गज ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की एक सकारात्मक रिपोर्ट का बड़ा हाथ रहा। अगर आप इस दिग्गज कंपनी में निवेश करने की सोच रहे हैं या आपके पोर्टफोलियो में यह शेयर पहले से है, तो बाजार के नए समीकरण समझना आपके लिए जरूरी है।

बुरे दौर से बाहर निकला सिगरेट कारोबार

हाल ही में सरकार द्वारा टैक्स में की गई बढ़ोतरी ने आईटीसी के सबसे अहम सिगरेट कारोबार की रफ्तार को धीमा करने की कोशिश की थी। हालांकि, जून तिमाही के नतीजे बता रहे हैं कि कंपनी इस चुनौती से उम्मीद से काफी बेहतर तरीके से निपट रही है। बाजार के जानकारों को आशंका थी कि सिगरेट की बिक्री (वॉल्यूम) में 10 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आएगी, लेकिन असल में यह गिरावट केवल 5 से 6 फीसदी तक ही सीमित रही। यह सच है कि टैक्स का ज्यादा बोझ उठाने की वजह से सिगरेट सेगमेंट के मुनाफे (EBIT) में सालाना आधार पर 35 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन, राहत की बात यह है कि कंपनी द्वारा कीमतों में धीरे-धीरे किए जा रहे बदलाव से मांग फिर से पटरी पर लौट रही है।

नोमुरा का बड़ा दांव, अपग्रेड हुई रेटिंग

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का साफ तौर पर मानना है कि आईटीसी के लिए सबसे बुरा वक्त अब खत्म हो चुका है। इसी भरोसे के साथ फर्म ने इस शेयर की रेटिंग को 'रिड्यूस' से अपग्रेड करके सीधे 'बाय' (खरीदें) कर दिया है। इसके साथ ही टारगेट प्राइस भी 300 रुपये से बढ़ाकर 340 रुपये कर दिया गया है। दूसरी तरफ, मोतीलाल ओसवाल ने थोड़ी सतर्कता बरतते हुए अपनी 'न्यूट्रल' रेटिंग और 300 रुपये का टारगेट कायम रखा है। मोतीलाल ओसवाल का तर्क है कि हालिया टैक्स बढ़ोतरी के असर को पूरी तरह सामान्य होने में अभी कुछ और तिमाहियों का समय लग सकता है। वहीं, जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने स्टॉक पर 'ऐड' (Add) रेटिंग तो बरकरार रखी है, लेकिन इसका टारगेट घटाकर 325 रुपये कर दिया है। उनका तर्क है कि कंपनी की 5 फीसदी की शानदार डिविडेंड यील्ड इस शेयर को बड़ी गिरावट से बचाने का काम करेगी।

एफएमसीजी से एग्री बिजनेस का हाल

अगर जून तिमाही (Q1FY27) के समग्र नतीजों पर नजर डालें, तो कंपनी का कुल रेवेन्यू 16,908 करोड़ रुपये रहा, जो बाजार के 17,362 करोड़ रुपये के अनुमान से थोड़ा कम था। कामकाज के मोर्चे पर कंपनी का EBITDA 4,514 करोड़ रुपये रहा और मार्जिन घटकर 26।7 फीसदी पर आ गया। कुल नेट प्रॉफिट 3,579 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि बाजार 3,990 करोड़ रुपये की उम्मीद कर रहा था। हालांकि, कंपनी के रोजमर्रा के सामान (FMCG) वाले कारोबार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 फीसदी की ग्रोथ हासिल की। इसके अलावा पेपरबोर्ड बिजनेस में भी 9% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से सप्लाई चैन पर असर पड़ा है, जिसके कारण एग्री बिजनेस का रेवेन्यू 17 फीसदी तक गिर गया।

निवेशकों के लिए ये है सलाह

कंपनी मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि सिगरेट बाजार में अपनी हिस्सेदारी बचाने के लिए कड़े और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। नोटबुक जैसे गैर-जरूरी एफएमसीजी उत्पादों की मांग में भी अब सुधार दिख रहा है, जो भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। बाजार के रुख की बात करें, तो आईटीसी को कवर करने वाले कुल 37 एनालिस्ट्स में से 17 अब भी इस शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 15 जानकारों की राय इसे 'होल्ड' करने की है, जबकि सिर्फ पांच ने इसे बेचने का सुझाव दिया है।

अमेरिका को पछाड़ भारत ने सोलर एनर्जी में दुनिया को दिखाया दम, बिजली की कीमत सुन रह जाएंगे हैरान

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में स्थापित सोलर एनर्जी क्षमता 2014 में सिर्फ 3 गीगावाट से बढ़कर 30 जून, 2026 तक 162.15 गीगावाट के स्तर पर पहुंच गई है, जो देश में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आए बड़े बदलाव को दिखाता है। यह जानकारी सरकार की ओर से रविवार को दी गई।

सरकारी फैक्टशीट में कहा गया है कि देश ने 2025 में 37 गीगावाट सोलर क्षमता जोड़ी, जिससे सालाना क्षमता बढ़ोतरी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर ग्रोथ मार्केट बन गया।

सोलर सेक्टर में सबसे अहम बदलावों में से एक पिछले दशक में बिजली की दरों में आई कमी है। यह 'ई-रिवर्स ऑक्शन' सिस्टम के जरिए हुई बोली की वजह से हुआ, जिसमें कंपनियां सबसे कम दर पर बिजली आपूर्ति करने के लिए मुकाबला करती हैं। जैसे-जैसे अधिक डेवलपर्स ने हिस्सा लिया, दरें 2010 में लगभग 18 रुपए प्रति यूनिट से घटकर 2.44 रुपए प्रति यूनिट के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गईं।

दरों में कमी ने सोलर पावर को काफी सस्ता बना दिया है। इसके चलते, भारत दुनिया के सबसे कम लागत वाले सोलर पावर मार्केट में से एक बनकर उभरा है। 2025 में, यूटिलिटी-स्केल सोलर पीवी से बिजली की 'लेवेलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी' (एलसीओई) 35 डॉलर प्रति मेगावाट थी, जो 44 डॉलर प्रति मेगावाट के ग्लोबल औसत से काफी कम है।

31 जुलाई, 2026 को 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' (पीएम-एसएसवाई) को मंजूरी मिलने से भारत के सोलर सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिला है। इस योजना का मकसद 'एनर्जी स्टोरेज सिस्टम' (ईएसएस) के साथ 5,000 मेगावाट के 'फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक' (एफएसपीवी) प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना है। कम से कम दो घंटे (10,000 मेगावाट) की स्टोरेज क्षमता वाला ईएसएस राज्यों को पीक डिमांड को मैनेज करने में और मदद करेगा। मौजूदा जलाशयों और इंडस्ट्रियल तालाबों का इस्तेमाल करके, यह योजना जमीन जैसे सीमित संसाधनों पर दबाव कम करेगी। यह इंटीग्रेटेड एनर्जी स्टोरेज के जरिए ग्रिड की विश्वसनीयता को भी बेहतर बनाएगी। 5,070 करोड़ रुपए के बजट के साथ, यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू की जाएगी।

भारत में बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स की स्थापित क्षमता 118.79 गीगावाट है। कुछ बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स में भादला सोलर पार्क (राजस्थान), पावगाडा सोलर पार्क (कर्नाटक) और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क (मध्य प्रदेश) शामिल हैं। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर सिस्टम से 27.88 गीगावाट की क्षमता मिलती है। बाकी क्षमता हाइब्रिड सोलर प्रोजेक्ट्स और ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम से आती है। हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में सोलर पावर के साथ बैटरी स्टोरेज या दूसरे पावर सोर्स का इस्तेमाल होता है, जबकि ऑफ-ग्रिड सिस्टम उन इलाकों में बिजली पहुंचाते हैं जो ग्रिड से नहीं जुड़े हैं।

देश की कुल गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 283.46 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें 274.68 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता शामिल है। 29 जुलाई 2025 को, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ने भारत की बिजली की 51.5 प्रतिशत मांग पूरी की, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक हिस्सा है।

ग्लासगो में कोप26 के दौरान, भारत ने 'पंचामृत' लक्ष्यों की घोषणा की, जिसमें 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य शामिल हैं।

अमेरिका में टैरिफ पर बवाल, नए टैक्स के खिलाफ 25 राज्यों ने दायर किया मुकदमा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के 25 राज्यों ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन के नए टैरिफ के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उनका कहना है कि ये टैरिफ उन इंपोर्ट टैक्स (आयात कर) की जगह लेने का एक बहाना हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में रद्द कर दिया था। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर 10% या उससे ज्यादा वाले टैरिफ लगाए थे।

अमेरिका का आरोप था कि इन देशों ने जबरदस्ती मजदूरी से बने सामान के आयात को रोकने के लिए काफी कदम नहीं उठाए। ये नए टैरिफ तब लागू हुए जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हार के बाद लगाए गए अस्थायी टैरिफ़ की समय-सीमा खत्म हो रही थी। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद, प्रशासन एक बार फिर टैरिफ के नए दौर के जरिए परिवारों और व्यवसायों पर गैर-कानूनी रूप से टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप का तर्क है कि ऊंचे टैरिफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने पिछले साल अमेरिका की उस दशकों पुरानी नीति को पलट दिया जो कम टैरिफ और ज्यादा आजाद व्यापार का समर्थन करती थी। 1977 के 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) का इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने लगभग हर देश से होने वाले आयात पर दोहरे अंकों वाले टैरिफ लगाए। उनका कहना था कि अमेरिका का लंबे समय से चला आ रहा व्यापार घाटा एक नेशनल इमरजेंसी के बराबर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि IEEPA के तहत टैरिफ लगाने की इजाजत नहीं है। इस फैसले के बाद प्रशासन को उन आयातकों को पैसे वापस करने पड़े, जिन्होंने टैरिफ का भुगतान किया था। खोए हुए राजस्व की भरपाई करने के लिए, ट्रंप ने दुनिया भर में 10 प्रतिशत के अस्थायी टैरिफ लागू किए। लेकिन 24 जुलाई की आधी रात को उनकी समय-सीमा खत्म हो गई। अब वह 'ट्रेड एक्ट ऑफ 1974' की धारा 301 के तहत ज़्यादा स्थायी टैरिफ लागू कर रहे हैं। यह धारा राष्ट्रपति को उन देशों पर आयात कर और अन्य प्रतिबंध लगाने की इजाजत देती है जो अनुचित व्यापार तौर-तरीके अपनाते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन पर भारी टैरिफ लगाने के लिए धारा 301 का इस्तेमाल किया था, और वे अदालती चुनौतियों में भी टिके रहे। प्रशासन ने जबरदस्ती मजदूरी से जुड़े टैरिफ लगाने के लिए धारा 301 का इस्तेमाल किया। ये टैरिफ 10 प्रतिशत से 12।5 प्रतिशत के बीच हैं और उन देशों पर लागू होते हैं जो अमेरिका में 99 प्रतिशत आयात भेजते हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा, अमेरिका अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल उन अनुचित कार्यों, नीतियों और तौर-तरीकों को खत्म करने के लिए कर रहा है जो अमेरिकी व्यापार पर बोझ डालते हैं। किसी दूसरे देश का जबरदस्ती काम करवाकर बनाए गए सामान के आयात पर रोक न लगाना और उसे ठीक से लागू न करना अनुचित है। इससे अमेरिकी व्यापार और अमेरिकी कामगारों पर बोझ पड़ता है।

भारत का खौफ! पाकिस्तान ने बॉर्डर पर तैनात की चीन की SH-15 आर्टिलरी, 50 किमी से ज्यादा मारक क्षमता

इस्लामाबाद, एजेंसी। भारत से लगी सीमा पर पाकिस्तान ने चीन की SH-15 155 मिलीमीटर/52 कैलिबर व्हील्ड सेल्फ-प्रोपेल्ड हॉवित्जर की तैनाती बढ़ाई है। हालांकि, भारत-पाकिस्तान सीमा पर SH-15 की कितनी संख्या तैनात की गई है, इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान के पास SH-15 की कुल करीब 12 से 13 रेजिमेंट हैं। पाकिस्तान ने अपनी रणनीतिक जरूरत और ऑपरेशनल तैनाती के हिसाब से इन आर्टिलरी सिस्टम को अलग-अलग मोर्चों पर बांटा है।

बताया जा रहा है कि SH-15 की कुछ रेजिमेंट भारत-पाकिस्तान सीमा के संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं, जबकि कुछ को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तैनात किया गया है। यानी पाकिस्तान इस चीनी आर्टिलरी सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ भारत से लगे मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि अपने दूसरे संवेदनशील इलाकों में भी कर रहा है। पाकिस्तान ने चीन से कुल 236 SH-15 गन का ऑर्डर दिया था और इनकी डिलीवरी साल 2022 से शुरू हुई। SH-15 एक ट्रक पर आधारित पहिएदार सेल्फ-प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है, जिसे तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर फायरिंग पोजिशन में तैनात किया जा सकता है। इसकी खासियत इसकी लंबी दूरी की मारक क्षमता है। रिपोर्टों के मुताबिक, रॉकेट-असिस्टेड प्रोजेक्टाइल के साथ SH-15 की रेंज 50 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। ऐसे में यह सीमा से काफी पीछे तैनात रहकर भी दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता रखती है। पाकिस्तान ने इस सिस्टम के लिए चीन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हासिल किया है। पाकिस्तान की Heavy Industries Taxila यानी HIT में SH-15 के घरेलू उत्पादन की क्षमता विकसित किए जाने की जानकारी सामने आई है। पाकिस्तान की ओर से SH-15 की तैनाती उसके आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। वहीं भारत भी अपनी आर्टिलरी क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना में ATAGS, K9 Vajra, Dhanush और M777 जैसे आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम शामिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत स्वदेशी Mounted Gun System यानी MGS को भी विकसित कर रहा है।

क्या शेख हसीना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में आ सकती है दरार?

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश ने भारत से साफ जवाब मांगा है कि 5 अगस्त को नई दिल्ली से होने वाले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वर्चुअल कार्यक्रम को लेकर उसका क्या रुख है। ढाका का कहना है कि वह भारत के साथ अच्छे और भविष्य पर आधारित रिश्ते चाहता है, लेकिन अगर भारत की जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों के लिए हुआ, तो दोनों देशों के संबंध प्रभावित हो सकते हैं।

बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, हसीना 5 अगस्त को नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया के एक कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय, पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नोफेल और बांग्लादेश ह्यूमन राइट्स वॉच के महासचिव मोहम्मद अली सिद्दीकी के भी शामिल होने की खबर है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अगले महीने 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आ सकते हैं। भारत सरकार ने उन्हें इस सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पर औपचारिक निमंत्रण भेजा है। अगर रहमान भारत आते हैं, तो फरवरी 2026 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ यह उनकी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय मुलाकात होगी। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत सरकार नहीं, बल्कि एक निजी संस्था आयोजित कर रही है। इसलिए फिलहाल बांग्लादेश इस पर नजर बनाए हुए है। अगर जरूरत पड़ी तो भारत के विदेश मंत्रालय से औपचारिक संपर्क किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पहले भी भारत को मौखिक और लिखित रूप से बता चुका है कि फरार या दोषी ठहराए गए लोगों को भारत की धरती से बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने वाली राजनीतिक गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने भी पहले संकेत दिया था कि ऐसे लोगों से भारतीय जमीन पर राजनीतिक बयान देने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत में रह रहे फरार लोग बांग्लादेश के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियां करते हैं, तो इससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश ऐसा नहीं चाहता और वह भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। उधर, प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी से मुलाकात में यही मुद्दा उठाया।

खाड़ी और होर्मुज संकट के बीच ईरान में भारत के नए राजदूत

तेहरान, एजेंसी। खाड़ी में जारी संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बने तनाव के बीच भारत ने ईरान के लिए नया राजदूत नियुक्त किया है। वरिष्ठ राजनयिक विश्वेश नेगी को ईरान में भारत का अगला राजदूत बनाकर भेजा जा रहा है। नेगी के शीघ्र ही तेहरान में अपनी नई जिम्मेदारी संभालने की उम्मीद है। नेगी अब रुद्र गौरव श्रेष्ठ की जगह लेंगे, जिन्हें अब तुर्की में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने कल सोमवार को ऐलान किया की कि भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अफसर विश्वेश नेगी को ईरान में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे विश्वेश नेगी को इस्लामी गणराज्य ईरान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।" वह 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। नेगी अभी विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। नेगी की राजदूत के रूप में नियुक्ति भारत और ईरान के बीच संबंधों के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच करीबी रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा संबंध हैं। राजदूत के रूप में नेगी के सामने तेहरान से पश्चिम एशिया में तेजी से बदलती क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति के बीच भारत के राजनयिक संबंधों को और मजबूत करने की होगी। भारतीय विदेश सेवा के 2002 बैच के अफसर विश्वेश नेगी वरिष्ठ राजनयिक हैं और उन्होंने अपने राजनयिक करियर के दौरान कई अहम पदों पर काम भी किया है। वे अभी विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, जहां वे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को संभालते हैं। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्रालय में नियुक्ति से पहले, नेगी रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) के रूप में काम कर रहे थे। इस दौरान, उन्होंने रक्षा कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सैन्य सहयोग का काम किया तथा अहम द्विपक्षीय रक्षा चर्चाओं में देश का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें आर्मेनिया के साथ सैन्य सहयोग और रक्षा औद्योगिक साझेदारी पर अहम बातचीत भी शामिल थी।

अपने राजनयिक करियर के दौरान, नेगी ने संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विभाग में निदेशक के तौर पर भी काम किया, जहां उन्होंने नीतिगत मामलों और अंतरराष्ट्रीय मसलों को बखूबी से संभाला। उन्होंने पाकिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर काम किया और बाद में संयुक्त सचिव के तौर पर ओशिनिया विभाग से जुड़े, इस दौरान उन्होंने उच्च-स्तरीय राजनयिक बातचीत का नेतृत्व किया, जिसमें भारत और पापुआ न्यू गिनी विदेश कार्यालय परामर्श शामिल था। नेगी के लिए नई नियुक्ति चुनौतीपूर्ण रहेगी क्योंकि पश्चिम एशिया में पिछले कुछ महीनों से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर सैन्य हमले किए गए थे, जिसके बाद तेहरान ने भी करारा जवाब दिया। संघर्ष शुरू होने के बाद सैन्य हमलों के अलावा, युद्धविराम का टूटना और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा।

परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ रांची में आंदोलन जारी, विधानसभा घेराव की तारीख अलग-अलग क्यों?

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में पेपर लीक से जुड़े मामले पर जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद अब झारखंड में भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। राजधानी रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की OMR शीट विवाद, 14वीं जेएसएससी-सीजीएल और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और भर्ती एजेंसियों में सुधार की मांग कर रहे हैं। इस बीच कई छात्र संगठनों ने विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है, लेकिन इन सभी की तारीख अलग-अलग है।

लगभग 10 दिनों से सैकड़ों की संख्या में छात्र रांची के कचहरी स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। ये छात्र संविधान की कॉपी लेकर जेपीएससी और जेएसएससी के भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं। धीरे-धीरे आंदोलनरत छात्रों को अलग-अलग राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलता जा हो रहा है। हालांकि सरकार की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने राज्य के कई ठिकानों पर रेड डाली है तो आयोग के पूर्व चेयरमैन से लगातार पूछताछ की जा रही है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल। खियांग्ते से सीआईडी अधिकारियों ने कल सोमवार को परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में करीब सात घंटे तक पूछताछ की। एजेंसी ने उनसे चौथी बार पूछताछ की है। इससे पहले 28 जुलाई को खियांग्ते से 9 घंटे, 29 और 31 जुलाई को 8-8 घंटे पूछताछ की गई थी।

प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितता और गड़बड़ियों की जांच सीआईडी की जगह सीबीआई से करवाई जाए। साथ ही 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाए और फिर से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा आयोजित कराई जाए। साथ ही परीक्षा कैलेंडर जारी किए जाएं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर कठोर कार्रवाई की जाए।

मुंडा स्टेडियम में अलग-अलग जगहों पर लगे टेंट

हालांकि मुंडा स्टेडियम में छात्रों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन अब गुटों में बंटता दिख रहा है। स्टेडियम में 2 अलग-अलग जगहों पर टेंट लगाया गया है। छात्रों का कहना है कि इस आंदोलन में राजनीतिक हस्तक्षेप और मतभेदों की वजह से ऐसा हुआ है। हालांकि, दोनों पक्षों के आंदोलनरत छात्रों की मांग एक ही है, लेकिन आंदोलन के संचालन, नेतृत्व और आगे की रणनीति को लेकर अलग-अलग राय सामने आने से इसकी एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। एकजुटता की कमी का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि छात्रों से जुड़ी मांग एक ही है, लेकिन 3 संगठनों ने अलग-अलग तारीखों पर विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है।

पीएसआई इंडिया को सीएसआर टाइम्स अवार्ड

मातृछाया कार्यक्रम के लिए गोल्ड तो हेल्थ फॉर आल प्रोग्राम के लिए मिला सिल्वर अवार्ड

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार के साथ मिलकर समुदाय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराने में सक्रिय रूप से सहयोग कर रही पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) संस्था को मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में सीएसआर टाइम्स अवार्ड से नवाजा गया। संस्था को रूरल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट की कैटेगरी में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया फाउंडेशन से वित्त पोषित "मातृछाया" कार्यक्रम के लिए गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके अलावा निवाबूपा हेल्थ इंश्योरेंस से वित्त पोषित हेल्थ केयर-हेल्थ फॉर आल (इंटिग्रेटेड प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी टिल दि लास्ट माइल) कार्यक्रम के लिए सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है।

पीएसआई इंडिया के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकेश शर्मा ने बताया कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से मातृछाया कार्यक्रम की अनूठी पहल उत्तर प्रदेश में की गयी है। इसके तहत पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग की मदद से बहराइच, बलरामपुर और हरदोई जिलों के एक-एक सीएचसी का चयन किया गया। इसके बाद वहां के प्रसव स्थल व प्रसव कक्ष की व्यवस्थाओं का मानक के अनुरूप आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण किया गया। इसके साथ ही प्रसव बिस्तरों, नवजात शिशु देखभाल क्षेत्र, नर्सिंग स्टेशन और सही तरीके से हाथ धुलने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया। इससे प्रसूता और नवजात को एक स्वस्थ और बेहतर माहौल प्राप्त हुआ । इसके लिए सीएसआर टाइम्स गोल्ड अवार्ड प्राप्त होने से निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े साथियों और संस्था का उत्साहवर्धन होगा और हमारा प्रयास होगा कि सेवाओं को और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए।

दूसरी ओर हरियाणा के गुरुग्राम में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर पीएसआई इंडिया और निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के सहयोग से चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित चार मेडिकल मोबाइल यूनिट को संचालित किया जा रहा है। मेडिकल मोबाइल यूनिट ग्रामीणों के सामान्य रोगों की जांच करने के साथ ही जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान करती है। इसके अलावा परामर्श और आवश्यकता पड़ने पर रेफर की भी सुविधा प्रदान करती है। हेल्थ फॉर आल कार्यक्रम के तहत किशोर-किशोरियों को इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलावों व एनीमिया से बचने के बारे में भी परामर्श प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए सीएसआर टाइम्स सिल्वर अवार्ड से संस्था को नवाजा गया है।

नेचुरल स्टार नानी की द पैराडाइस के टीजर की रिलीज डेट आउट, यश की टॉक्सिक से पहले मचाएगी धमाल

2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में शामिल द पैराडाइस अपने दमदार बज को लगातार बनाए हुए है. नैचुरल स्टार नानी पर फिल्माया गया इसका ब्लॉकबस्टर गाना आया शेर पहले ही चार्टबस्टर बन चुका है. वहीं, फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो ने भी अपने बोल्ड और रॉ अंदाज से सभी का ध्यान खींचा था. खास तौर पर उस दमदार डायलॉग ने, जिसमें लीड किरदार को एक वेश्या का बेटा बताया गया था और वही बात उसके हाथ पर भी लिखी हुई नजर आई थी.

द पैराडाइस इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में से एक बन चुकी है. फिल्म के ऐलान के बाद से ही इसे लेकर जबरदस्त चर्चा है. नैचुरल स्टार नानी लीड रोल में नजर आएंगे और फिल्म अपने दमदार फर्स्ट लुक पोस्टर्स, शानदार प्रमोशनल मटेरियल और पावरफुल म्यूजिक की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. वहीं, दसरा की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद नानी और निर्देशक श्रीकांत ओडेला की जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है, जिससे द पैराडाइस 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल हो गई है.

जहां फिल्म का चार्टबस्टर गाना आया शेर यूट्यूब पर 20 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल कर इंटरनेट पर छा चुका है और एक कल्चरल फिनॉमिना बन गया है, वहीं अब दर्शकों की नजरें फिल्म के बहुप्रतीक्षित टीजर पर हैं, जो 6 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार ह. माना जा रहा है कि यह टीजर अब तक की सबसे चौंकाने वाली झलक होगी, जो फिल्म के बोल्ड और रॉ अंदाज को सामने लाएगी और इसे लेकर लोगों का उत्साह और बढ़ा देगी.

निर्देशक ने अपने सोशल मीडिया पर टीजर की एक दमदार झलक शेयर करते हुए लिखा -द पैराडाइस का टीजर 6 अगस्त. मेकर्स ने भी अपने सोशल मीडिया पर यह दमदार झलक शेयर करते हुए लिखा -1 मिनट 35 सेकेंड का पागलपन तैयार है. प्तञ्जद्धद्गक्कड्डह्म्ड्डस्रद्बह्यद्ग का टीजर 6 अगस्त को रिलीज होगा. जादल ज़माना के लिए तैयार हो जाइए.

इस शानदार उपलब्धि के साथ-साथ इस गाने को यूट्यूब पर 18 लाख लाइक्स भी मिल चुके हैं, जो दर्शकों के बीच इसकी जबरदस्त लोकप्रियता को दिखाता है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर छाने से लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की पसंद बनने तक, आया शेर ने द पैराडाइस को लेकर लोगों का उत्साह और बढ़ा दिया है. फिल्म की रिलीज से पहले इसका क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है.

एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले बनी द पैराडाइस 21 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत कुल आठ भाषाओं में रिलीज की जाएगी. वहीं, फिल्म को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मेकर्स ने हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसे प्रेजेंट करने के लिए संपर्क किया है. दमदार निर्देशक, शानदार स्टारकास्ट और बड़े विजन के साथ द पैराडाइस सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बनने की ओर बढ़ रही है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

अभिनेत्री अदिति बालन की फिल्म जीडीएन से पहला लुक जारी, इस किरदार में आएंगी नजर

निर्देशक कृष्ण कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म जीडीएन सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है। इसी बीच, मेकर्स ने अभिनेत्री अदिति बालन का लुक भी जारी किया। मेकर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभिनेत्री का पहला लुक जारी कर लिखा, पेश है, पद्मावती के रूप में अदिति बालन। एक आवाज, स्टैंड और ऐसी कहानी, जो सब कुछ बदल देती है। यह फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार हैं। यह फिल्म मशहूर भारतीय आविष्कारक, किसान और समाजसेवी जी.डी. नायडू के जीवन पर आधारित है, जिसमें अभिनेत्री अदिति बालन पद्मावती की भूमिका अदा करती हुई सभी को मनोरंजन करेंगी।

मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज कर दिया है, जिसमें महान आविष्कारक गोपालस्वामी दोरैस्वामी नायडू (जीडी नायडू) के जीवन, संघर्ष और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी असंदिग्ध बगावत की एक रोमांचक झलक दिखाता है। इसकी शूटिंग मुख्य रूप से कोयंबटूर में की गई है, जहां नायडू ने अपनी कर्मभूमि बनाई थी।

ट्रेलर की शुरुआत स्वतंत्रता-पूर्व काल के उन चुनौतीपूर्ण दौर से होती है, जहां भारत के एडिसन कहे जाने वाले जीडी नायडू के अपरंपरागत विचारों और आविष्कारों को सत्ताधारी ब्रिटिश हुकूमत और ताकतवर ताकतों द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद एक ब्रिटिश अधिकारियों को यह कहते हुए दिखाया गया है कि नायडू नाजियों और जर्मनी के साथ व्यापार कर रहे हैं, जो क्राउन के खिलाफ यानी राजद्रोह है। उन पर कर चोरी और अन्य मनगढ़ंत आरोप भी लगाए जाते हैं।

कृष्णकुमार रामकुमार द्वारा निर्देशित जीडीएन में आर. माधवन मुख्य भूमिका में हैं, जिन्हें भारत का एडिसन कहे जाने वाले जी.डी. नायडू के रूप में देखा जा सकता है। फिल्म में माधवन के अलावा जयराम, प्रियामणि, दुशारा विजयन, सत्यराज, अदिति बालन, विजय राय और टीजे अरुणासलम भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत गोविंद वसंत ने दिया है और सिनेमैटोग्राफी अरविंद कमलानाथन ने की है।

यह फिल्म 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि फिल्म को दर्शक किस कदर प्यार देते हैं।

ट्रोलिंग के बाद भूमि पेडनेकर ने मारा यू-टर्न? अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वाली युवती के बचाव में कही ये बात

बीते दिनों नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन में कुछ युवाओं ने कथित तौर पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। इसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने भी बीते दिन एक वीडियो साझा करके छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा का विरोध किया। इस पर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। इसके बाद आज सोमवार को भूमि ने एक और वीडियो साझा किया है।

युवा छात्रा को मिल रही धमकियों पर भूमि क्या बोलीं?

भूमि पेडनेकर ने अपने हालिया वीडियो में प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करने वाली एक नाबालिग छात्रा का बचाव किया है। उन्होंने छात्रा को मिलने वाली धमकियों की निंदा करते हुए कहा है कि यह स्वीकार्य नहीं है। रेप और जान से मारने की धमकियां किसी भी तरह से मंजूर नहीं। न ही इस तरह की नेगेटिविटी। आइए, यह सब बंद करें।

भूमि ने लोगों से की एकजुट होने की अपील

वीडियो में भूमि पेडनेकर ने कहा है कि उन्होंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा, जिसमें एक युवा लड़की इंटरव्यू दे रही थी। यह वही बच्ची थी, जो छात्र प्रदर्शन का हिस्सा थी। वीडियो वायरल होने के बाद से उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। भूमि पेडनेकर ने लोगों से बच्ची का ऑनलाइन उत्पीड़न बंद करने, मानसिक सेहत का ध्यान रखने और नफरत के बजाय एकजुट होकर अपनी बात रखने की अपील की है। भूमि ने कहा, 'हम सब बस एक ही चीज चाहते हैं कि देश की तरक्की हो। देश का भला हो। अगर हम सब एकजुट होकर, एकता के साथ अपनी बात सही तरीके से रखेंगे, तभी हम सच में सकारात्मक बदलाव देख पाएंगे'।

नेटिजंस ने भूमि से क्या कहा?

अभिनेत्री के इस वीडियो पर भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इसे यूजर्स 'डैमेज कंट्रोल' का नाम दे रहे हैं। वहीं, कुछ यूजर्स भूमि को सुझाव दे रहे हैं कि वे अपने अभिनय पर ध्यान दें। कुछ यूजर्स ने दावा किया कि भूमि को अपने फॉलोअर्स कम होने का आभास हुआ है, शायद इसलिए उन्होंने दूसरा वीडियो शेयर किया है। वहीं, कुछ यूजर्स लिख रहे हैं, 'भूमि प्लीज अब आप रील्स साझा करनी बंद करिए'।

क्यों फूटा भूमि पर नेटिजंस का गुस्सा?

सवाल है कि आखिर भूमि पेडनेकर को ट्रोल क्यों किया जा रहा है? दरअसल, बीते दिन उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा की आलोचना की थी। भूमि ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो जारी कर कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। इस पर भी उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com